नई दिल्ली

09 जुलाई, 2026 गुरूवार

मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 98

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

मेरी पहली प्राथमिकता ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलना : कमिंस 07

संक्षिप्त वार्ता

वांगचुक 11 दिन से भूख हड़ताल पर, 7 किलो से अधिक वजन घटा

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के दौरान 11 दिनों से अनशन पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है। बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन सात किलोग्राम से अधिक घटकर 59.40 किलोग्राम रह गया है।

वांगचुक की सेहत पर डॉक्टरों का कहना था, कि उनका रक्तचाप और ब्लड शुगर सामान्य सीमा में हैं तथा शरीर में पानी की कमी नहीं है, लेकिन लगातार उपवास के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा संगठन के एक्स हैंडल पर लगी रोक हटाने के फैसले का भी आंदोलनकारियों ने स्वागत किया है। प्रदर्शन स्थल पर आइसा के कई कार्यकर्ता भी अलग मंच से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

समोसे के लिए रोक दी ट्रेन, रेलवे ने शुरू की जांच कार्रवाई

इन्दौर। समोसे के लिए ट्रेन रोकने के सोशल साइट्स पर एक वायरल विडियो के बाद रेलवे ने संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विडियो इन्दौर के समीप राऊ का है जहां महू से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन राऊ-रंगवासा क्षेत्र के पास करीब 10 मिनट तक रुकती है और इस दौरान लोको पायलट समोसे-कचोरी लेने उतरते हैं। और फिर ट्रेन रवाना हो जाती है। कल हुई लोको पायलट के तरह ट्रेन रोक समोसा लेने की पूरी घटना का किसी ने विडियो बना इस दावे के साथ वायरल कर दिया कि रोजाना का घटनाक्रम है। जब रेलवे अफसरों के पास यह विडियो पहुंचा तो उनका कहना है कि मंगलवार को ही ऐसा हुआ है। रोजाना ऐसा नहीं होता है। और यह मालगाड़ी का ड्राइवर था। संबंधित विभाग को इसकी जांच के लिए भेजा गया है। यदि जांच में किसी कर्मचारी की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह से महापौर ने की मुलाकात

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइटों पर चल रहे बायोमाइनिंग एवं वेस्ट प्रोसेसिंग कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर महापौर ने तीनों लैंडफिल साइटों की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपते हुए परियोजनाओं के विभिन्न आयामों से अवगत कराया।

मप्र में पानी के साथ-साथ हो रही है सौगातों की बारिश

मध्यप्रदेश में आया लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वेब वार्ता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' स्कीम मध्यप्रदेश के लिए एक लक्ष्य की तरह है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अगले ढाई सालों में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगी। हमारी सरकार ने देश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार खोल दिए हैं। पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' है। मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी अन्तर्गत इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे इंसेंटिव्स को धरातल पर उतारने में पीथमपुर का बड़ा योगदान है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशक आयें, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम पीथमपुर में मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी के लिए एक पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पीथमपुर को भावी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तथा वैश्विक निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। हम यहां ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिल्स और टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक की पूरी चेन तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लिउगोंग इंडिया कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उदघाटन समारोह में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मौजूदा उत्पादन ईकाई के विस्तारित कार्य का उद्घाटन

किया। लिउगोंग कंपनी द्वारा यहां अपनी मौजूदा उत्पादन इकाई में 272 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश कर नए प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड के प्रेसीडेंट (चेयरमैन) श्री झेंग जिन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत-अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, धरातल पर डेवलपमेंट लाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का मैन्युफैक्चरिंग गेटवे बन चुका है। एक माह में पीथमपुर में दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनी द्वारा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा मध्यप्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने लिउगोंग समूह और सभी कंपनी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह नई इकाई प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को मध्यप्रदेश की धरती से एक नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन दिनों वर्षा के साथ-साथ हर दिन नई-नई सौगातों की भी बारिश हो रही है। मात्र 10 दिनों में प्रदेश में 5 ऐतिहासिक औद्योगिक आयोजन हुए हैं, जो यहां हो रहे औद्योगिक विकास की नई तस्वीर दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में बीते 2 वर्षों में ही करीब 10 हजार करोड़ रूपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के यह आंकड़े विरोधी दलों को जवाब है। लिउगोंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट के विस्तार के लिए भी पीथमपुर को ही चुना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि लिउगोंग कंपनी दुनिया के सबसे बड़े हैवी अर्थ मूवर्स प्रोड्यूसर्स में से एक है। लगभग 2 दशकों से पीथमपुर में कार्यरत लिउगोंग की इस नई उत्पादन इकाई से कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,250 मशीनों से बढ़कर 7,500 मशीनों तक पहुंच जाएगी। इस विस्तार से 600 प्रत्यक्ष तथा सहायक उद्योगों एवं सप्लाई चेन के माध्यम से 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस प्लांट में उत्पादन प्रारंभ होते ही भारतीय उद्योगों से लिए जाने वाले कंपोनेंट्स में कंपनी की हिस्सेदारी भी 40 प्रतिशत से बढ़कर अब 60 प्रतिशत हो जाएगी, जिससे प्रदेश के एमएसएमई, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में ही मध्यप्रदेश को 76 हजार 862 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से 82 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। इसमें नर्मदापुरम में सबसे अधिक 11 हजार 500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। पिछले छह महीने में ही मप्र में 41 हजार 950 करोड़ के निवेश से जुड़ी 166 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन इकाइयों के बनने से लगभग 50 हजार नए रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पीथमपुर ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री का भी प्रमुख केंद्र है। यहां लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले साल सितंबर में धार में ही देश के पहले पीएम मित्र पार्क की नींव रखी थी। टेक्सटाइल सेक्टर का यह पीएम मित्र पार्क मालवा और निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

मुस्लिम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार

वेब वार्ता, नई दिल्ली

इस्लाम धर्म अपनाने वालों को आरक्षित वर्ग के तहत प्राप्त आरक्षण के लाभ को खत्म करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि इस्लाम धर्म अपना लेने वाला व्यक्ति पिछड़े वर्ग के तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसको लेकर तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। गो-हत्या पर रोक हटाने की मांग के बाद तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अधिसूचित समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) मानने का आदेश जारी किया था। यही नहीं, तत्कालीन स्टालिन सरकार ने

हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी जारी करना शुरू कर दिया था, जिन मुस्लिम जातियों को यह आरक्षण दिया जा रहा था उनमें- अंसार, दक्कनी मुस्लिम, दुबेकुला, लब्बाइस, रोवथर, मराकायार, मपिल्ला, शेख और सैयद शामिल हैं।

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पीबी बालाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी आदेश उन न्यायिक निर्णयों के पूरी तरह से खिलाफ हैं, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन न्यायिक फैसलों के मुताबिक धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ मुसलमान ही माना जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने इस मामले में 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है।

2 हजार साइकिलों के साथ इंदौर से होगी भोपाल तक की यात्रा

वेब वार्ता, भोपाल। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांग्रेस की इंदौर की भोपाल तक की साइकिल यात्रा में जीतू पटवारी के साथ हर जिले से 2 हजार साइकल सवार शामिल होंगे। हालांकि पटवारी इंदौर से लेकर भोपाल तक अकेले ही साइकल चलाकर पहुंचेंगे। शुरूआत आरएनटी मार्ग स्थित यूनिवर्सिटी से सुबह 7 बजे होगी।

कांग्रेस इसी माह अपना एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जेन-जी को साथ लेकर यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर मोहल्लों और वार्ड स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। जो साइकिल चला सकते हैं, उन्हें साथ लेकर यह यात्रा शुरू होगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि 14 जुलाई की सुबह 7 बजे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ साइकिल यात्रा शुरू होगी, जिसमें शहर कांग्रेस की ओर से 2 हजार साइकिलें शामिल होंगी। आरएनटी मार्ग स्थित यूनिवर्सिटी परिसर से ये यात्रा निकलकर रीगल चौराहा, हाईकोर्ट, लैंटर्न चौराहा, मालवा मिल चौराहा, सयाजी चौराहा, विजय नगर, सत्यसांई चौराहा, देवास नाका, लसूड़िया, बायपास टर्न, मांगलिया, डकाच्या, शिप्रा होते हुए देवास जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। ये सभी कार्यकर्ता पटवारी के साथ साइकिल चलाते हुए उन्हें शहर की सीमा तक छोड़ने जाएंगे। इसी बीच एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साइकिल चलाते हुए शामिल होंगे। शिप्रा से देवास जिले के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में शामिल हो जाएंगे।

हर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होते जाएंगे, पटवारी अकेले ही चलेंगे

अमरनाथ यात्रा: रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उमड़े, 6 जत्थे में 8 हजार से अधिक रवाना

जम्मू। पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। मंगलवार को यात्रा के छठे जत्थे में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 8,815 श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुए। इन श्रद्धालुओं को बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों तक पहुंचाने के लिए कुल 363 वाहनों का एक विशाल काफिला तैनात हुआ। जिला प्रशासन अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के पहले चार दिनों में ही 86 हजार से अधिक श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जिससे इस वर्ष यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है।

रोहिणी में निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली, वेब वार्ता। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 स्थित पॉकेट जी-5 में एमसीडी विद्यालय के पीछे बुधवार शाम एक निमार्णाधीन पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस, दमकल विभाग और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रहे हैं।

दमकल विभाग के अनुसार घटना की सूचना शाम 4:19 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया तथा मलबे में फंसे

लोगों की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बीच अचानक पूरी इमारत ढह गई, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद एहतियातन आसपास के लगभग 50 मीटर क्षेत्र में स्थित मकानों को खाली करा दिया गया है। राहत दल ने अब तक दो लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे के नीचे 5 से 10 लोग और फंसे हो सकते हैं।

प्लेटफॉर्म की छत से झरने की तरह गिरा पानी, यात्री परेशान

भोपाल स्टेशन की बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

वेब वार्ता, भोपाल। राजधानी में हुई तेज बारिश के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला। स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म की छत से अचानक तेज धार के साथ पानी गिरने लगा। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया और यात्रियों को सामान के साथ निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म की छत से लगातार तेज गति से पानी बहता रहा। उस समय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी खड़ी थी, जिससे यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई यात्री पानी से बचते हुए प्लेटफॉर्म पार करते नजर आए। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में प्लेटफॉर्म की छत से झरने जैसी तेज धार में पानी गिरता दिखाई दे रहा है। इसके बाद रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लगातार तेज बारिश के कारण प्लेटफॉर्म शेड पर जमा पानी की निकासी के लिए बने ड्रेनेज होल अवरुद्ध हो गए थे। निकासी बाधित

होने से पानी छत पर जमा होता गया और बाद में एक साथ प्लेटफॉर्म पर गिरने लगा। ऐसी स्थिति प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 5 के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिली, जहां छत से पानी टपकता रहा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की ऐसी ही घटना करीब दो वर्ष पहले भी सामने आई थी। लगातार दोहराई जा रही इस समस्या के बाद यात्रियों का कहना है कि मानसून से पहले स्टेशन की छत और जल निकासी व्यवस्था का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।

इंजीनियरिंग टीम ने किया सुधार कार्य

घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधन ने इंजीनियरिंग टीम को मौके पर भेजा। टीम ने ड्रेनेज सिस्टम की जांच कर अवरुद्ध निकासी मार्ग को साफ कराया, जिसके बाद पानी का रिसाव बंद हो गया। अधिकारियों का कहना है कि असामान्य रूप से तेज बारिश के कारण यह स्थिति बनी थी और शिकायत मिलते ही व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया।

हटते नहीं...हटा दिए जाते चंपत राय और अनिल मिश्रा

वेब वार्ता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों के पीछे की असल वजह सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार, इन इस्तीफों का मुख्य कारण राम मंदिर ट्रस्ट के कड़े नियम थे, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई पदाधिकारी या ट्रस्टी गड़बड़ी या अनियमितता का दोषी पाया जाता है, तब पद से हटाया जा सकता है।

सूत्रों ने खुलासा किया है कि पद से हटने की संभावना को देखकर राय और मिश्रा ने संभावित कार्रवाई से ठीक पहले अपने इस्तीफे दे दिए। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, किसी भी पदाधिकारी या ट्रस्टी को हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरुत होती है। यद्यपि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष

इस्तीफे पर खुला बड़ा राज

गोविंद गिरी ने सार्वजनिक रूप से इन इस्तीफों को नैतिक आधार पर दिया गया बताया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट उन्हें हटाने की पूरी तैयारी में था। इस बीच, राम मंदिर की प्रशासनिक और बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अयोध्या में कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के साथ दो नए सहयोगी, जगदीश और चंदन राय, नियुक्त किए गए हैं। अब राम मंदिर के बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय संयुक्त रूप से करने वाले है। बैंक से जुड़े किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए इन तीनों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए है। पहले बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी और उनके ही हस्ताक्षर मान्य होते थे, जबकि गोविंद गिरी के केवल डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग होता था।

3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं

सुरक्षा व्यवस्था को भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया गया है। अब दान गणना स्थल पर कुल 43 लोग मौजूद रहने वाले हैं, और निगरानी के लिए 13 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ पहले कैमरे नहीं थे। दान पेटी से गणना स्थल तक धनराशि सुरक्षित रूप से लाने के लिए 27 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगी है। इसके अतिरिक्त, दान पेटी और गणना स्थल के बीच विभिन्न पिलरों के पास पुलिस बल की अलग से तैनाती की जाएगी। पिलर नंबर 34 के पास, जहाँ एक गुप्त दान पेटी रखी गई है, वहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत तीन अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

अस्पतालों की लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त करोड़ों की मेडिकल मशीनें खा रहीं धूल

वेब वार्ता, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर महंगी मेडिकल मशीनें खरीदी गईं, लेकिन इनमें से कई मशीनें सालों से धूल खा रही हैं। न मरीजों को इनका फायदा मिल रहा है और न ही इन पर खर्च हुए सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।

हाई कोर्ट ने इसे जनता के पैसे की बबार्दी बताते हुए दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों को ऐसी मशीनों की जांच कराने का आदेश दिया है, जो खरीदी तो गईं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहीं।

अदालत के सामने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 15.42 करोड़ रुपये की पीईटी साइक्लोट्रॉन मशीन का मामला आया था, जो अप्रैल 2022 से बंद पड़ी है। इसके बाद कोर्ट ने सभी अस्पतालों में ऐसी मशीनों का

ऑडिट कराने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल यह जांच करें कि कौन-कौन सी मशीनें खरीदी गईं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना होगा।

संपादकीय

निष्कलंक का इस्तीफा क्यों?

अंततः राम मंदिर ट्रस्ट को अपने महासचिव रहे चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार करने पड़े। इस निर्णय में मजबूरी झलकती रही, क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने चंपत राय को महापुरुष और संत-साधु करार दिया। ट्रस्ट ने चंपत को आरोपित ही नहीं किया। ट्रस्ट ने बैठक में यह जरूर स्वीकार किया कि राम मंदिर के प्रबंधन में कई खामियां थीं, लिहाजा चंदा-चढ़ावे की चोरी-डकैती संभव हो सकी। कई अनियमितताएं और विसंगतियां थीं, लिहाजा हृदय से ही दान का धन गिनते रहे और 70 बार चोरी करते रहे। यह विशेष जांच दल का शुरूआती निष्कर्ष बताया गया है। इस महापाप से सभी आहत, दुखी और लज्जित हैं। राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं, भव्य राम मंदिर की छवि धूमिल, कलंकित हुई है, उसकी भरपाई सिर्फ इस्तीफों से नहीं की जा सकती। चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत समूचा ट्रस्ट परोक्ष रूप से दोषी है, आरोपित है, लिहाजा ट्रस्ट को भंग करके नई व्यवस्था तय करनी चाहिए थी। यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की थी, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि ट्रस्ट संघ परिवार की बपौती है, उसकी प्रासंगिक, धार्मिक ईकाई ही बना रहेगा। वर्चस्व आरएसएस, विहिप और संघवादी संतों का ही रहेगा, लिहाजा संघ के बुनियादी प्रचारक रहे दो चेहरे बाहर करने पड़े, तो उनका विकल्प भी संघवादी कृष्ण मोहन को चुना गया। भारतीय वन सेवा अधिकारी रहे कृष्ण मोहन 2012 से ही आरएसएस में सक्रिय हैं और प्रचारक भी रहे हैं। अब उन्हें राम मंदिर का पवित्र दायित्व सौंपा गया है। अभी उन्हें अंतरिम महासचिव कहा जा सकता है। ट्रस्ट ने यह विमर्श नहीं किया कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्रा को इतना निरंकुश और ताकतवर किसने और क्यों बनने दिया गया? उनकी मनमानियां कैसे चलती रहीं? करीब 114 करोड़ रुपए के भूमि-सौदे उन्हें ही क्यों करने दिए गए, जबकि इन जमीनों की कीमत 20-25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है? क्या यह बड़ा घोटाला नहीं है?

ट्रस्ट सामूहिक जिम्मेदारी का संगठन होता है, लिहाजा समूचा ट्रस्ट ही बदलना चाहिए था। जो साधु-संत किस्म के चेहरे ट्रस्ट में हैं, उन्हें प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय अंकुश और निगरानी का कोई अनुभव नहीं है, तो फिर करोड़ों रुपए के दान, चंदे, चढ़ावे का दायित्व उन्हें क्यों सौंपा गया? राम मंदिर आंदोलन के दौरान असंख्य लोगों ने योगदान दिया था, राम-राम के उद्घोष किए थे, बलिदान भी दिए थे, उनमें से अधिकतर मंदिर की सीमा से बाहर ही हैं। वे भी आज पीड़ित, व्यथित होंगे! आंदोलन की सक्रियता ट्रस्ट में शामिल होने की गारंटी नहीं है। संविधान में तो यह प्रावधान नहीं है कि ट्रस्ट में सिर्फ संघ परिवार की ही सदस्यता होगी। हिंदू तो गैर-संघी भी हो सकता है और प्रशासनिक अनुभव का धनी भी हो सकता है, लेकिन राम मंदिर पर संघ का ही अघोषित कब्जा है। सवाल यह भी गंभीर है कि चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर किया जा रहा था, तो बैठक में उनका अभिनंदन क्यों गाया गया? कोषाध्यक्ष गोविंद देव ने उन्हें निष्कलंक और निरापराधी माना है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान और ट्रस्ट के बाद चंपत राय की सेवाओं, कार्यों, तप-त्याग और भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। चंपत राय से असावधानी में भूल हो गई, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्या गोविंद देव कोई न्यायाधीश हैं, जो ऐसा फैसला सुनाया है? क्या ट्रस्ट के स्तुतिगान के बाद अब चंपत राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ केस नहीं बनेगा और वह निष्कलंक होकर अयोध्या से विदा हो सकेंगे? क्या विहिप में वह उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे? ऐसे पाक-साफ व्यक्ति का ट्रस्ट ने इस्तीफा क्यों मंजूर किया? दरअसल हमें तो ट्रस्ट की बैठक ही प्रायोजित और लीपापोती वाली ज्यादा लगी। हालांकि गोविंद देव ने कुछ बेशकीमती वस्तुएं ही सार्वजनिक की हैं। ऐसी 2926 वस्तुएं बताई जा रही हैं। अनुमान तो यह भी कहता है कि चांदी को गलाने, दान की गई वस्तुओं का स्वरूप बदलने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं है। फिर ऐसा क्यों किया गया? ट्रस्ट ने भारत सरकार की मिंट से अनुबंध क्यों किया? ऐसे कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। देखते हैं कि नई व्यवस्था क्या फैसले लेती है? जहां तक विपक्ष का संबंध है, वह इस मामले पर आंदोलित है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

ठहरा हुआ सावन, प्रकृति का आत्म-संगीत

आधुनिकता की सुख-सुविधाएं केवल मूर्ख एवं अपरिपक्व व्यक्तियों को सुहा सकती हैं। संवेदनशील एवं परिपक्व व्यक्ति तो सुखानुभूतियों को प्रकृति के अनुकूल उपक्रमों में ही ढूंढता है। इस बार प्रकृति चौमासा बनकर यह सुख बरसा रही है। जीवन के भौतिक परिवेश में सावन की गतिविधियां अनुगुंजित हैं। वायु प्रवाह मधुर है। वायु की शीतलता ब्रह्मौषधि के समान प्रवाहित है।

दो दिवसों से शांत वर्षा हो रही है। काया, मन तथा आत्मा तीनों प्रसन्न हैं। पहले के दुःख समाप्त हैं, पीड़ाएं ध्वस्त हैं और क्षोभ अस्तित्वहीन है। विषाद तो जैसे था ही नहीं, इतना आनंद दे रही है यह शांत वर्षा। परिवेश समशीतोष्ण है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नभ पर फव्वारा लगा हुआ है और उससे ध्वनिहीन अणु-अणु बूंदें गिर रही हैं। प्रातःकाल से श्रावण की यह छवि आरंभ हो जाती है तथा दिवसभर रहती है। इस श्रावणी स्वरूप के सम्मुख चैत्र, फाल्गुन एवं वसंत भी न्यून सुंदर प्रतीत होते हैं। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु ऐसी नहीं होती। इस वर्ष मेरे जैसे जीवों का भाग्य बलवान था, जो वर्षण का ऐसा प्रशांत सौंदर्य देखने को मिल रहा है। वायुमंडल, भूमि, सागर, वनों, सरिताओं, वनस्पतियों, वृक्षों, लताओं तथा जीवों को ऐसा ही अनुकूल वर्षण चाहिए होता है। किंतु प्राकृतिक विकृतियों के कारण ऐसा प्रतिवर्ष होना अब संभव नहीं है। इस वर्ष के श्रावण में ऐसा संभव हुआ है, तो यह पंचतत्वों तथा जीवों का सौभाग्य है। भूमि तत्व में समाहित समस्त उप-तत्व वर्षा की बूंदों में स्नान कर संतृप्त हैं। व्योम तत्व के अंतर्गत अस्तित्वावान सभी उप-तत्व अणुस्वरूप जलधाराओं में भीगकर शीतलता एवं विनम्रता के प्रतिनिधि बने हुए हैं। जल तत्व पावस में मिश्रित होकर अधिक पवित्र हो उठा है।

वायु तत्व ने इस श्रावणी पर्यावरण में नीरयुक्त पुष्पों का स्पर्श प्राप्त कर लिया है। अग्नि तत्व समशीतोष्ण हो उठा है। श्रावण का प्रभाव ऐसा है कि आधुनिकता एवं इसकी समस्त गतिविधियां अकस्मात व्यर्थ प्रतीत होने लगी हैं तथा तीस-चालीस वर्ष पूर्व का मानवीय जीवन और उसकी गतिविधियां विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं में स्पंदित होने लगी हैं। विशेषकर चार दशक पहले का प्राकृतिगत ग्राम्य जीवन आत्मस्मृतियों में प्रवाहित होने लगा है। इस पावसवृष्टि की अनुकूलता, सौंदर्य-गूढ़ता तथा प्रशांत-सौम्यता ने मन-मस्तिष्क को सुख का एक नया ठिकाना दिया है। ऐसा सुख पहले कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा सुख आधुनिकता कभी भी नहीं दे सकती। आधुनिकता की सुख-सुविधाएं केवल मूर्ख एवं अपरिपक्व व्यक्तियों को सुहा सकती हैं। संवेदनशील एवं परिपक्व व्यक्ति तो सुखानुभूतियों को प्रकृति के अनुकूल उपक्रमों में ही ढूंढता है। इस बार प्रकृति चौमासा बनकर यह सुख बरसा रही है। जीवन के भौतिक परिवेश में सावन की गतिविधियां अनुगुंजित हैं। वायु प्रवाह मधुर है। वायु की शीतलता ब्रह्मौषधि के समान प्रवाहित है। जिसे भी यह औषधि स्पर्श करती है, वह स्वयं को स्वास्थ्य के शिखर पर खड़ा महसूस करता है। वसुंधरा पर तैरती जलधारें जीवों के लिए आकर्षण का पर्याय बनी हुई हैं। वे बाधामुक्त होकर विद्यमान हैं, वे क्रीड़ाताल बनी हुई हैं। पक्षियों की चहचह, कूक, कुहूक, गान, चीची, चूचू में नवीन समुत्साह है। गगन का छत्र धरती पर श्रावण की चुनरी ओढ़ता प्रतीत होता है। गगन पर विहार करते नीरयुक्त मेघ नवल शोभा के साथ चलायमान हैं। वायुक्षेत्र अलौकिक स्वप्नलोक बना हुआ है, उस पर उड़ने की अभिलाषाएं बलखा रही हैं। संवेदनाओं का उत्ताल वेग मन से बाहर आने को व्यग्र है। जीवन के विविध इंद्रधनुषी रंग साक्षात होकर आनंदानुभूतियों को झूला झुला रहे हैं। इस जीवनानुभव में, आधुनिकता को छोडकर, व्यतीत पचास, चालीस, तीस एवं बीस वर्षों का मानवीय जीवन आनंद गति के साथ बलखा रहा है।

उसी जीवन के ऋतु पर्याय के रूप में यह श्रावण झूम रहा है, संवेदनशील मानवों को झुमा रहा है, जीवन जीने की नैसर्गिक कला सिखा रहा है और जीवन में आनंद अनुभव करने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। स्वयं के साथ, जीवन के साथ, प्राकृतिक जीवन के साथ तथा सर्वोपरि श्रावण ऋतु के दैवीय रूप-स्वरूप के साथ एकाकार होकर सुख के पुष्पों में झूलने का अवसर दे रहा है। यह जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। इसे आत्मसात करने पर जीने का अर्थ महान बन जाता है। इसे सतत स्वीकार करने पर जीने का अभिप्राय आनंदलोक बन जाता है। अत्यंत आत्मभावन है यह ठहरा हुआ सावन। इतनी मृदुलता है इस सावन की, व्योम से गिरती नीर बूंदों में कि संवेदनशील मनुष्य एक क्षण में ही आत्मप्रत्यर्पित हो जा रहा है और आधुनिक जीवन की समस्त गतिविधियों से विमुख होकर प्राकृतिक सावन के उपक्रमों से बंध जा रहा है। यह पावस काल जीवंत है, इसमें अमृत है। इसमें वन-वनस्पतियों के साथ जुड़ने का आवाहन है। यह दुविधाहीन है, यह पंचतत्वों की आनंदपूर्ण सुविधा है। यह प्रकृति रत्न वास्तव में अमूल्य है। निस्संदेह इन्हें भौतिक रूप में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, किंतु भावनात्मक रूप में तो सहेज व संभाल कर रखा ही जा सकता है। इन्हें गीत, संगीत, राग, कविता, साहित्य, धर्म, शिक्षा, कला, सभ्यता, आनंद तथा सर्वोपरि जीवन के आनंद प्रतिनिधि के रूप में तो अंगीकार-स्वीकार किया ही जा सकता है। श्रावण की ऐसी संगति जीवन की प्रतिकूलताओं, दुर्गुणों, अवगुणों, रोग-शोक देने वाले कारकों, उदासी में वृद्धि करने वाले रहस्यों तथा मानवों में पारस्परिक समस्याएं व संघर्ष बढ़ाने वाले कारणों पर एक आनंद-प्रहार है। सावन की ऐसी शांत-प्रशांत गति जीवन के सम्मुख चुनौती बनकर खड़े प्रत्येक अवरोधक पर एक मधुरतम आक्रमण है। अभिलाषा है कि ऐसा श्रावण प्रतिवर्ष आए तथा मनुष्यों के तन-मन सहित उनकी आत्मा को भी सुखानंद में डुबाये। रे मानव! तू एक क्षण अनुभव तो कर यह ठहरा हुआ, शांत, सुभाषित, वातानुकूलित, समशीतोष्ण, इंद्रधनुषी, पारलौकिक श्रावण।

सावन के शांत वर्षण पर उत्पन्न अनुभूतियों से ये दो कविताएं सृजित हुईं: (1) वर्षा बूंदें रिमझिम-रिमझिम/गाये धरती हरितिम-हरितिम। हरियाली हर-हर विस्तार/शीतलता श्रावण उपहार। जायें पीछे सौ वर्षों में/वर्षा होती थी आनंदी। देखें अब इन वर्षों में/वर्षण होता है उन्मादी। सावन का वो रंग उड़ गया/छूट गया वो सुंदर रूपक। सुगंधित सुरभित ऋतुचर्या/होती नहीं धरा पर व्यापक। देखा श्रावण समय उपस्थित/सामान्य समझ में 'पावसावृत्त'। ऋतु विशिष्टताओं से संचित/अद्भुत रूप भू का श्रृंगारित। पौराणिक आस्था आधार/देवाधिदेव का समवविहार। जगजीवन की आवश्यकता/नीरवृष्टि फल उत्पादकता। श्रावण चरमोत्कर्ष विचित्र/मानव मन संवेदन संचित्र। योगवृत्ति युक्त अंतःस्थल/दर्शन अध्यात्म आत्मसंबल। वर्षा होती बूंदें गिरतीं/चलते वायु झंकोरे। भू-नभ मैत्री बढ़ती रहती/हे! मानव हर्षित हो रे। चक्षु जागरण अपरंपार/भू-नभ पर श्रावण संसार। धूप-छांव का मधुरिम रीत/भूतल से नभ को है प्रीत। ॥ (2) धुंध नहीं तुहिन भी अविद्यमान/रजत वर्षा बूंदें गिरतीं अविराम। जलबूंदों के असंख्य हार/भू को अम्बर का उपहार। नदियां नहर पोखर जलाशय/नीर संचयन संशोधन आशय। इन्द्रधनुष का रंगाकर्षण/रंग-बिरंग सतरंग संप्रेषण। देख इसे ग्रामीण का कहना/अब न होगा दो दिन बरसना। सघन श्वेत प्रशांत मेघदल रहे भटक/डोलते यहां-वहां जाते नीर टलहट। बरसा-बिखरा-बहता-ठहरा जल लेकर/पुनः लौट आते नभ में अपने-अपने घर। नील व्योम के पदचिह्न बनकर/घन बैठे रंगपट्टियों से सजकर। रात इधर शीतल धरती पर/घनहीन गगन उत्तुंग ऊपर। जुगनू टिमटिमाते वसुधा के इधर/कुलकुसुम व्योम का चंद्रमा उधर। उसके साथ चमचम करते सितारे/मैं बेकल व्योम देखते नयन बेचारे।

विकेश कुमार बडोला
स्वतंत्र स्तंभकार

बांग्लादेश की बदलती सैन्य सोच और भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौती

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारियों में गिने जाते रहे हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय में भारत की निर्णायक भूमिका रही थी। दोनों देशों ने दशकों तक सुरक्षा, व्यापार, जल बंटवारे, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग किया। किंतु पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति, उसकी सैन्य सोच और विदेश नीति में दिखाई दे रहे बदलावों ने नई चिंताओं को जन्म दिया है। विशेष रूप से बांग्लादेशी सेना में धार्मिक प्रतीकों और इस्लामी पहचान को अधिक प्रमुखता देने की खबरों ने भारत सहित पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है।

हाल के घटनाक्रमों के अनुसार बांग्लादेशी सेना की कुछ नई बटालियनों का नाम इस्लामी इतिहास के शुरूआती खलीफाओं के नाम पर रखा गया है और सेना के पारंपरिक राष्ट्रवादी नारों के स्थान पर धार्मिक नारों को महत्व दिए जाने की चर्चा भी सामने आई है। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो यह केवल सैन्य परंपरा का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश की बदलती वैचारिक दिशा का संकेत भी माना जाएगा। किसी भी सेना का चरित्र केवल उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, प्रतीकों और प्रशिक्षण से भी निर्धारित होता है।

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामी संगठनों और धार्मिक समूहों का प्रभाव बढ़ने की चर्चा लगातार हो रही है। लंबे समय तक अवामी लीग ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और जय बांग्ला की भावना को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाया था। अब यदि सेना के भीतर धार्मिक पहचान को अधिक महत्व दिया जा रहा है तो यह उस वैचारिक परिवर्तन का हिस्सा माना जा सकता है जो देश की राजनीति और समाज में भी दिखाई दे रहा है।

बांग्लादेश की इस बदलती सोच के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण घरेलू राजनीति है। किसी भी देश की सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान अपने समर्थक सामाजिक वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं। यदि इस्लामी संगठनों का प्रभाव बढ़ता है तो सेना सहित अन्य संस्थाओं पर भी उसका प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक माना जाता है।

दूसरा कारण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है। बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। रक्षा उपकरणों की खरीद, सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास इसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। इससे वह अपने रक्षा विकल्पों को व्यापक बनाना चाहता है ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।

तीसरा कारण भारत के साथ कुछ पुराने और नए विवाद भी हैं। सीमा पर अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, जल बंटवारा, व्यापारिक असंतुलन तथा राजनीतिक बयानबाजी जैसे मुद्दों ने समय-समय पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह भारत विरोधी भावनाओं को घरेलू राजनीति में समर्थन जुटाने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरा बांग्लादेश या उसकी पूरी जनता भारत विरोधी है। वहां बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक, बुद्धिजीवी और व्यापारी भी हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंधों को अपने देश के हित में मानते हैं।

भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा का है। यदि भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं या सीमा क्षेत्रों में तनाव का वातावरण बनता है तो उसका सीधा प्रभाव असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर पड़ सकता है। भारत पहले ही सीमा पर आधुनिक निगरानी व्यवस्था, बाड़ और सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत कर चुका है। ऐसे में किसी भी प्रकार की उकसाने वाली गतिविधि या घुसपैठ की संभावना पर स्वाभाविक रूप से गंभीर नजर रखी जाएगी।

अवैध घुसपैठ भी लंबे समय से भारत के लिए एक संवेदनशील विषय रही है। भारत ने हाल के वर्षों में सीमा प्रबंधन को अधिक सख्त बनाया है और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया है। इस कारण दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर समय-समय पर तनाव की स्थिति बनी है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी अवैध गतिविधि के लिए पूरे समुदाय या पूरे देश को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होता। सीमा सुरक्षा और कानून का पालन दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है।

जहां तक मुस्लिम खलीफाओं के नाम पर सैन्य इकाइयों के गठन का प्रश्न है, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। समर्थकों का तर्क हो सकता है कि यह केवल धार्मिक और ऐतिहासिक प्रेरणा का विषय है, जबकि आलोचक इसे सेना के बढ़ते वैचारिक और धार्मिक झुकाव के रूप में देखते हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना आवश्यक होगा कि भविष्य में बांग्लादेश की सैन्य नीति, प्रशिक्षण और व्यवहार किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए इस समय सबसे उपयुक्त नीति सतर्कता और संयम की होगी। मजबूत सीमा सुरक्षा, आधुनिक खुफिया तंत्र, प्रभावी कूटनीति और आर्थिक सहयोग के माध्यम से ही क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। पड़ोसी देश बदले नहीं जा सकते, इसलिए दीर्घकालिक समाधान टकराव नहीं बल्कि संतुलित संबंधों में ही निहित है। साथ ही भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर पूरी तैयारी और सावधानी बनाए रखनी होगी।

बांग्लादेश की वर्तमान नीति को केवल भारत विरोध के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। उसके निर्णयों के पीछे घरेलू राजनीति, इस्लामी दलों का बढ़ता प्रभाव, बदलता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रक्षा संबंध तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करने की इच्छा जैसे अनेक कारक भी काम कर रहे हैं। फिर भी यदि धार्मिक पहचान को सैन्य संरचना का प्रमुख आधार बनाया जाता है और सीमा क्षेत्रों में अनावश्यक आक्रामक संदेश दिए जाते हैं, तो इससे अविश्वास बढ़ सकता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

भारत और बांग्लादेश दोनों का भविष्य शांति, सहयोग और पारस्परिक सम्मान में ही सुरक्षित है। इतिहास ने दोनों देशों को एक-दूसरे का स्वाभाविक पड़ोसी बनाया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मतभेदों को संवाद से सुलझाया जाए, सीमा सुरक्षा को मजबूत रखा जाए और किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ या उग्र राष्ट्रवाद को क्षेत्रीय शांति पर हावी न होने दिया जाए। यही नीति दोनों देशों तथा पूरे दक्षिण एशिया के दीर्घकालिक हित में होगी।

लेखक- कांतिलाल मांडोत
(एल 103 जलवन्त टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324
वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार)

धर्म का धन : श्रद्धा की अमानत, स्वार्थ का साधन नहीं

समाज की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है, तो वह उसकी आस्था है। धन, सत्ता, ज्ञान और संसाधन समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु जिस समाज की आस्था जीवित रहती है, वह समाज हर संकट से उबरने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मंदिर, स्थानक, तीर्थ, उपाश्रय और धर्मस्थल केवल ईंट-पत्थरों से निर्मित भवन नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, तप, त्याग और विश्वास के जीवंत केंद्र होते हैं।

एक श्रद्धालु जब धर्मस्थल में प्रवेश करता है, तो वह केवल पूजा करने नहीं आता; वह अपने मन की व्यथा, आशा, कृतज्ञता और विश्वास भी वहीं अर्पित करता है। उसकी दक्षिणा केवल मुद्रा नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई, उसके परिवार का विश्वास और धर्म के प्रति उसका समर्पण होता है। इसलिए धर्मस्थलों में आने वाला प्रत्येक अंश समाज की अमानत है।

दुर्भाग्य तब उत्पन्न होता है, जब धर्म के नाम पर प्राप्त धन या संसाधनों का उपयोग धर्म के उद्देश्य से हटकर व्यक्तिगत लाभ, वैभव, प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए होने लगे। यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं होती, बल्कि समाज की आस्था पर कुठाराघात होता है। जिस धन में हजारों श्रद्धालुओं की भावनाएँ जुड़ी हों, उसका दुरुपयोग केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और अंतरात्मा का भी विषय है।

इतिहास साक्षी है कि धर्म का धन कभी किसी को स्थायी सुख नहीं दे पाया। जो संपत्ति छल, विश्वासघात या धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अर्जित होती है, वह बाहर से भले वैभव का प्रदर्शन करे, पर भीतर शांति नहीं दे सकती। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि अनुचित साधनों से प्राप्त धन अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म के धन के संदर्भ में यह बात और भी अधिक सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें केवल धन नहीं, असंख्य लोगों की श्रद्धा समाहित होती है।

जैन दर्शन के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मानवता को संयम, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का अमूल्य संदेश दिया। इनमें अपरिग्रह का सिद्धांत विशेष रूप से आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। अपरिग्रह का अर्थ केवल अधिक वस्तुएँ न रखना नहीं है; इसका वास्तविक अर्थ है—लोभ, स्वार्थ, संग्रह की मानसिकता और अधिकार के दुरुपयोग से स्वयं को मुक्त करना।

यदि धर्म से जुड़े व्यक्ति ही अपरिग्रह को भूल जाएँ और धर्म को संग्रह, प्रभाव या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन बना लें, तो भगवान महावीर के संदेश का सार ही समाप्त हो जाता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि उसके अहंकार को छोटा करना है। धर्म हमें अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व सिखाता है; संग्रह नहीं, समर्पण सिखाता है; स्वार्थ नहीं, सेवा का मार्ग दिखाता है।

धर्मस्थलों का निर्माण समाज के सहयोग से होता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी-सी बचत से दान देता है, कोई किसान अपनी उपज का अंश अर्पित करता है, कोई व्यापारी अपनी आय का हिस्सा धर्मकार्य में लगाता है। सभी की भावना एक ही होती है—धर्म जीवित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी इन मूल्यों से जुड़ी रहें। ऐसे में यदि उस विश्वास को ठेस पहुँचती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज आहत होता है।

आज आवश्यकता आरोप लगाने या विवाद बढ़ाने की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की है। धर्मस्थलों का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। आय-व्यय का स्पष्ट लेखा-जोखा, समाज के प्रति जवाबदेही और धर्म के उद्देश्य के अनुरूप संसाधनों का उपयोग—ये केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएँ नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादाएँ हैं।

समाज को भी यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा केवल दान देने से नहीं होती, बल्कि धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने से होती है। जहाँ पारदर्शिता है, वहाँ विश्वास बढ़ता है; जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहीं धर्म फलता-फूलता है। यदि कहीं त्रुटि दिखाई दे, तो उसका समाधान भी धर्मसम्मत, संयमित और संवादपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कटुता, आरोप और वैमनस्य किसी भी धार्मिक वातावरण को शुद्ध नहीं बना सकते।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति से बड़ा धर्म है, पद से बड़ी मर्यादा है और संस्था से बड़ी आस्था है। व्यक्ति बदल सकते हैं, व्यवस्थाएँ बदल सकती हैं, परंतु धर्म और उसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। यदि धर्म की पवित्रता सुरक्षित रहेगी, तो समाज का विश्वास भी अडिग रहेगा।

भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव संग्रह में नहीं, त्याग में है; अधिकार में नहीं, उत्तरदायित्व में है; और बाहरी संपत्ति में नहीं, अंतःकरण की निर्मलता में है। यही संदेश आज प्रत्येक धार्मिक संस्था, प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक श्रद्धालु के लिए समान रूप से प्रासंगिक है।

आइए, संकल्प लें कि धर्म को कभी स्वार्थ का साधन नहीं बनने देंगे। मंदिर, स्थानक और तीर्थ केवल भवन नहीं, हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। उनकी पवित्रता, पारदर्शिता और मर्यादा की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। जब धर्म शुद्ध रहेगा, तभी समाज सुदृढ़ रहेगा; और जब आस्था सुरक्षित रहेगी, तभी संस्कृति अमर रहेगी।

लेखक- श्रमण डॉ पुष्पेन्द्र

आलेख

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध, बड़ी चुनौती

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और ह्यडिजिटल इंडियाह्ण तथा ह्यविकसित भारत-2047ह्ण का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन वित्तीय ठगी, फिशिंग, पहचान की चोरी, निवेश घोटाले, व्यक्तिगत गोपनीयता पर सेंध, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था, वही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उसे अपने हित में ढाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है।

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे, अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप सीमाओं, भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है।

चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दावा करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण, अश्लीलता, साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता।

साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस, बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शुरूआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है।

डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है। विशेष एजेंसियां, अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था और कठोर दंडात्मक कानून वहां की व्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत को भी इसी दिशा में और अधिक सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। स्थानीय पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का प्रशिक्षण देना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। तकनीक जितनी उन्नत होगी, अपराधी भी उतने ही नए तरीके खोजेंगे। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। लोगों को संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया के छल-प्रपंचों से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सुरक्षा का पूरा दायित्व नागरिक पर डालकर सरकार, बैंक और डिजिटल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकतीं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना संस्थागत दायित्व है।

भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर केवाईसी व्यवस्था भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। यदि फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलते हैं, यदि भुगतान प्लेटफॉर्म समय पर संदिग्ध लेन-देन नहीं रोकते, यदि आंतरिक मिलीभगत से अपराधियों को सुविधा मिलती है, तो यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट, कठोर उत्तरदायित्व और सख्त दंड व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साइबर अपराध अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। इंटरनेट की दुनिया में अपराधी सीमाओं से मुक्त हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की प्रमुख शक्तियों को साइबर अपराध के विरुद्ध साझा कानूनी ढांचा, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा। जिस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग आवश्यक माना गया, उसी प्रकार साइबर अपराध के विरुद्ध भी विश्वव्यापी समन्वय समय की मांग है।

अंततः डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। डिजिटल भारत की वास्तविक शक्ति उसके ऐप्स, सर्वरों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित है, जिसके साथ करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपने मोबाइल पर एक-एक लेन-देन करते हैं। आज आवश्यकता केवल तकनीकी समाधान की नहीं, बल्कि तकनीक, नैतिकता, कानून और उत्तरदायित्व के समन्वित मॉडल की है। सरकार को कठोर कानून, त्वरित न्याय और सक्षम जांच तंत्र विकसित करना होगा, डिजिटल कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा, वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ानी होगी और नागरिकों को डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा। साइबर अपराध और भारतीय डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन ही विकसित भारत की सबसे बड़ी कसौटी है। यदि यह संतुलन स्थापित हो गया, तो डिजिटल भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है, अन्यथा तकनीकी उपलब्धियां भी अविश्वास के बोझ तले दम तोड़ देंगी।

(लेखक - ललित गर्ग
(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

घर खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों पर ईडी के छापे

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीददारों से कथित धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन कंपनियों -सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड, नाइनेक्स डेवलपर्स लिमिटेड और मंजू जे होम्स (इंडिया) लिमिटेड झ से जुड़ी कम से कम पांच जगहों पर छापेमारी की गई।

करीब तीन साल बाद दिल्ली बाल अधिकार आयोग का पुर्नगठन

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) का पुनर्गठन करते हुए ओम प्रकाश व्यास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यास के अलावा राहुल गौतम, कुंदन कंसकर, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

जलभराव रोकने और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर सरकार सख्त

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर आगामी वर्षा ऋतु के दौरान जलभराव की रोकथाम, कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं तथा सरकारी विद्यालयों के सुधार कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को जलभराव वाले क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

डेम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि सरकार नियमित रूप से तैयारियों की समीक्षा कर रही है ताकि जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को कांवड़ शिविरों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, विद्युत और सुगम यातायात जैसी आवश्यक सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस माह से दौड़ने लगेगी पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी इस माह से पटरी पर दौड़ने लगी। उत्तर रेलवे ने इसका उद्घाटन करने के लिए अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।इस निर्देश में अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि उन्हें क्या भूमिक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान निभानी है। पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी का उद्घाटन कार्यक्रम जींद स्टेशन पर होगा। यह गाड़ी जींद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसका किराया 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक रहने की संभावना है। यह सफर एक घंटे का होगा।

जानकारी के अनुसार पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी के परिचालन को लेकर सभी एनओसी मिल चुकी हैं। इसका सफर ट्रायल हो चुका है। 10 कोच वाली इस गाड़ी का उद्घाटन इस माह जींद स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। उत्तर रेलवे का दिल्ली डिवीजन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई से पहले इस रेलगाड़ी का उद्घाटन हो सकता है। इसके साथ ही तीन अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन को लेकर भी उत्तर रेलवे तैयारी कर रहा है। यह स्टेशन मोदी नगर, शामली और नरवाना है जिन्हें अमृत भारत योजना के तहत नये स्वरूप में तैयार किया गया है।

संगम विहार में प्लास्टिक पैकिंग फैक्ट्री धधकी आग, तीन घंटे में पाया काबू

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित होली चौक इलाके में बुधवार दोपहर एक प्लास्टिक डब्बे की पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग से उठते धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जिस फैक्ट्री में आग लगी वह अवैध रूप से संचालित गत्ता एवं प्लास्टिक पैकिंग यूनिट बताई जा रही है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई। दिल्ली दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दोपहर 11:52 बजे मिली। सूचना मिलते ही शुरूआती तौर पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए लगातार अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। खबर लिखे जाने तक 15 से अधिक दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थीं।

बारिश के बावजूद आग की तीव्रता कम नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने कई दिशाओं से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन करीब तीन घंटे बाद भी आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी थी। अधिकारियों के अनुसार, फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक और पैकिंग सामग्री के कारण आग बार-बार भड़क रही थी। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए हैं। आग पूरी तरह बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा और यह भी जांच होगी कि फैक्ट्री वैध रूप से संचालित हो रही थी या नहीं।

हेडगेवार अस्पताल में जल्द शुरू होगा 'सखी' वन स्टॉप सेंटर, एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को जल्द ही हेडगेवार अस्पताल में एक ही स्थान पर सभी जरूरी सहायता मिल सकेगी। अस्पताल परिसर में वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। केंद्र शुरू होने के बाद हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा उपचार, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे महिलाओं को अलग-अलग कार्यालयों और संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा उन्हें समय पर समन्वित सहायता मिल सकेगी।

जूते में छिपाकर लाई जा रही 320 ग्राम सोने की सिल्लियां जब्त

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान से आई एक महिला यात्री को जूतों में सोने की सिल्लियां छिपाकर तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने महिला के कब्जे से लगभग 320 ग्राम वजन की 5 सोने की सिल्लियां बरामद की हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, महिला यात्री तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात से दिल्ली पहुंची थी। संदिग्ध गतिविधियों और हाव-भाव के आधार पर उसे सीमा शुल्क के हरित मार्ग को पार करने के बाद जांच के लिए रोका गया। प्रारंभिक जांच के दौरान महिला के सामान की क्ष-किरण जांच में कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई नहीं दी। लेकिन जब वह धातु का पता लगाने वाले द्वार से होकर गुजरी तो यंत्र ने संकेत दिया, जिसके बाद अधिकारियों को उस पर संदेह और गहरा हो गया। अधिकारियों ने महिला से जूतों की भी क्ष-किरण जांच कराने को कहा।

पहली बारिश में डूबे रास्ते, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में हुई तेज बारिश के बाद अनेक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने पर विपक्ष ने सरकार की मानसून तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नालों की सफाई और जलभराव रोकने के सरकारी दावे पहली ही बारिश में गलत साबित हो गए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा नालों की सफाई और जलभराव रोकने के संबंध में किए गए दावे केवल कागजों तक सीमित रहे। उनका कहना था कि कई प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। करावल नगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली ही बारिश में अनेक स्थानों पर जलभराव ने व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। उनके अनुसार आईटीओ, लाजपत नगर, मयूर विहार, पांडव नगर भूमिगत मार्ग, महरौली-बदरपुर मार्ग, सदर बाजार तथा आउटर रिंग मार्ग सहित कई क्षेत्रों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी।

मंत्री सिरसा ने राजौरी गार्डन के विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों से की चर्चा

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को राजौरी गार्डन विधानसभा का दौर करके स्थानीय लोगों से यहां के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने इलाके की सड़कों के नवीनीकरण का उद्घाटन वहां की जनता के हाथों कराया। यह जानकारी सिरसा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की।

मंत्री सिरसा ने कहा कि ये सड़कें उनकी हैं और इस विकास के सबसे बड़े हकदार भी वही हैं। विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें जनता की भागीदारी दिखाई दे। उन्होंने कहा कि राजौरी गार्डन के विकास की यह यात्रा यहां स्थानीय लोगों सहयोग से लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इससे पहले मंत्री सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में वीर चक्र से सम्मानित कर्नल अमरिक सिंह के घर जान करके उनके पोर्ट्रेट का अनावरण किया। इस मौके पर उनके बेटे कैप्टन हरबख्श सिंह (सेवानिवृत्त) और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सिरसा ने उनके वीरता पदक और उनसे जुड़ी स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा और बलिदान की जीवंत परंपरा है। ऐसे वीर सपूतों की गाथाएं हमें याद दिलाती हैं कि भारत की शक्ति उसकी सेना के शौर्य, परिवारों के त्याग और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण में बसती है।

ईंधन मूल्य को लेकर भाजपा पर आप का हमला

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में तत्काल राहत की संभावना कम बताई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विश्वास नगर वार्ड अध्यक्ष सुभाष चंद्र लाला ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और ईंधन की कीमतों में कमी का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम अधिक होने से परिवहन खर्च बढ़ता है, जिसका सीधा असर फल, सब्जियों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है।

कथित दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने जीटीबी अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बुधवार को राजधानी के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल के बाहर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपये के कथित दवा और स्वास्थ्य घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान आआपा के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले तीन दिनों से आआपा के नेता राजधानी के अलग-अलग अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को दवाओं में 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी दे रहे है। आआपा दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की दवाई खरीदी और उसके लिए 400 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 100 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ का कमीशन सरकार ने खाया। 103 करोड़ का कमीशन एक्स-रे मशीन पर खाया, 50 करोड़ का कमीशन चादर में खाया। ऐसे करके इस सरकार ने 650 करोड़ का घोटाला किया है।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि 650 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया और सारे घोटाले का असली गुनहगार राजीव रंगीला है वही सारे घोटाले का मास्टरमाइंड है जिसे एक महीने पहले एसीबी ने देश से जर्मनी भागा दिया। भारद्वाज ने दावा किया कि लगभग 10 लाख रुपये की अनुमानित बाजार कीमत वाली एक एक्स-रे मशीन को करीब 33 लाख रुपये में खरीदा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल की बेड शीट और कई अन्य मेडिकल सामान भी उनकी असल कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर खरीदे गए, जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। आआपा ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने, कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

दिल्ली के व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में जाम कम करने के लिए 38 नए पार्किंग स्थल चिन्हित

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 6,100 से अधिक वाहनों की संयुक्त क्षमता वाले 38 नए पार्किंग स्थलों की पहचान की है। इसके साथ ही निगम के अधिकार क्षेत्र में अधिकृत पार्किंग स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 445 हो जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि नए पार्किंग स्थलों को जोड़ने का उद्देश्य राजधानी के व्यस्त व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार, एमसीडी अपने 12 जोन में 408 पार्किंग स्थलों का संचालन करता है, जिनकी कुल क्षमता 84,000 से अधिक वाहनों की है। इनमें लगभग 52,000 चार पहिया वाहनों, 30,000 दुपहिया वाहनों तथा 1,386 बसों और ट्रकों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया, ह्यह्यनए चिन्हित किए गए 38 पार्किंग स्थलों पर 4,723 चारपहिया, 1,311 दुपहिया तथा 148 बसों और ट्रकों को पार्क किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए इस सप्ताह निविदाएं जारी की जाएंगी। नए पार्किंग स्थलों में सबसे बड़ी सुविधा द्वारका सेक्टर-14 में वेगास मॉल के निकट स्थित एक स्थान पर विकसित की जाएगी, जहां 806 वाहनों की पार्किंग क्षमता होगी। इसी क्षेत्र में ब्रिटिश सैलून-ककरोला मोड़ से द्वारका मोड़ सर्विस लेन तक स्थित एक अन्य प्रमुख पार्किंग स्थल पर 700 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी।

शाहदरा दक्षिण जोन के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित कई भूखंडों और सड़क किनारे के हिस्सों को मिलाकर 1,800 से अधिक नए पार्किंग स्थान विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा करोल बाग, रोहिणी, सिटी एसपी, दक्षिण, पश्चिम, मध्य, सिविल लाइंस और केशव पुरम जोन में भी नए पार्किंग स्थलों की पहचान की गई है। अधिकारियों के अनुसार, एमसीडी के सभी जोन में केंद्रीय जोन की पार्किंग क्षमता सबसे अधिक है। यहां 54 पार्किंग स्थलों, जिनमें 27 क्लस्टर पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं, पर 23,000 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है।

केशव पुरम जोन में 56 पार्किंग स्थलों पर 9,135 वाहनों तथा शाहदरा उत्तर जोन में 74 पार्किंग स्थलों पर 8,785 वाहनों के लिए पार्किंग की क्षमता है।

दक्षिण जोन में 41 पार्किंग स्थलों पर 8,087 वाहनों, करोल बाग जोन में 51 स्थलों पर 7,995 वाहनों, सिटी एसपी जोन में 46 स्थलों पर 6,884 वाहनों, पश्चिम जोन में 29 स्थलों पर 6,803 वाहनों तथा रोहिणी जोन में 11 स्थलों पर 6,492 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। सिविल लाइंस जोन में आठ पार्किंग स्थलों पर 1,671 वाहनों तथा नजफगढ़ जोन में आठ पार्किंग स्थलों पर 1,367 वाहनों के लिए पार्किंग की क्षमता है।

द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंग में मामूली टक्कर के बाद मारपीट, टैक्सी चालक फरार

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका एक्सप्रेसवे की सुरंग के भीतर एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद दो वाहन चालकों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान सफेद रंग की मारुति अर्टिगा टैक्सी के चालक ने कथित तौर पर डंडे से दूसरे वाहन चालक पर हमला करने का प्रयास किया।

यह घटना मंगलवार शाम करीब 7:55 बजे हुई। हालांकि, घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। शुरूआती जानकारी के अनुसार, यह घटना टैक्सी और वैगन-आर कार चालाकों के बीच मामूली टक्कर के बाद शुरू हुई। बहस के दौरान, वैगन-आर चालक ने कथित रूप से अपना बचाव करते हुए टैक्सी चालक को धक्का दिया जिससे वह लड़खड़ाकर पास में खड़ी एक अन्य गाड़ी किआ सेल्टोस से टकरा गया।

इस टक्कर से खड़ी गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद, पुलिस के आने से पहले ही टैक्सी चालक वहां से फरार हो गया। किआ सेल्टोस के मालिक और वैगनआर चालक ने मौके पर ही आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया। किसी को चोट नहीं आई और किसी भी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की। दिल्ली पुलिस के कापसहेड़ा पुलिस थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार टैक्सी चालक की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए सुरंग के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। मामले की जांच जारी है।

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन, यूजीसी कानून और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर होगी रणनीति तैयार

नई दिल्ली, वेब वार्ता

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आगामी 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित करने जा रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह और संरक्षक कृपा शंकर सिंह के मार्गदर्शन में होने वाली इस बैठक में देशभर के पदाधिकारी और युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों, विशेष रूप से शिक्षा नीति और राजनीतिक भागीदारी पर एक साझा और ठोस रणनीति तैयार करना है।

यूजीसी कानून और प्रमुख मांगें

बैठक का मुख्य एजेंडा नई यूजीसी (वत्रह्ल) व्यवस्था का विरोध करना है। संगठन का तर्क है कि नई व्यवस्था में योग्यता के बजाय श्रेणी को प्राथमिकता देने से मेधावी छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त, महासभा ने केंद्र सरकार और संघ प्रमुख मोहन भागवत को ज्ञापन भेजकर राजपूत समाज के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल और विधाई सदनों में समाज के लिए उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है।

ऐतिहासिक योगदान और भविष्य की रणनीति

संगठन ने अपने पत्र में देश के निर्माण और रक्षा में राजपूत समाज के ऐतिहासिक बलिदानों को रेखांकित किया है। महासभा ने राष्ट्र निर्माण में समाज के योगदान को याद दिलाते हुए आह्वान किया है कि राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह बैठक केवल समस्याओं को उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखने और भविष्य में समाज की दिशा तय करने के लिए एक निर्णायक मंच के रूप में देखी जा रही है।

केजरीवाल ने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लिखा पत्र, एक हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली, वेब वार्ता

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इथेनॉल20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कंपनियां एक सप्ताह के भीतर लिखित जवाब दें कि 2023 से पहले की पेट्रोल गाड़ियों में ई20 का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं।

अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पत्र लिखकर ई20 पेट्रोल को लेकर उनके दावों पर लिखित जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि मारुति, टोयोटा और हीरो को अलग पत्र भेजा गया है क्योंकि 4 जुलाई को हुई सरकारी पत्रकार वार्ता में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि पुरानी गाड़ियों में ई20 के इस्तेमाल से केवल 3-5 प्रतिशत माइलेज कम होती है और वाहन को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने

दावा किया कि इन कंपनियों के ओनर मैनुअल में 2023 से पहले के कई मॉडलों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई10 से ऊपर) के उपयोग की अनुमति नहीं है।

केजरीवाल ने कहा कि कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी वास्तविक आधिकारिक नीति क्या है। उन्होंने सभी कंपनियों से यह भी पूछा कि यदि ई20 के इस्तेमाल से किसी उपभोक्ता की माइलेज 5-10 प्रतिशत से अधिक घटती है या वाहन के किसी पुर्जे को नुकसान पहुंचता है, तो क्या कंपनियां इसकी भरपाई करेंगी।

उन्होंने बताया कि बाकी 26 कंपनियों को भी सामान्य पत्र भेजा गया है, जिसमें ई20 को लेकर उनकी स्थिति, संभावित माइलेज पर असर और वाहन को होने वाले नुकसान के बारे में स्पष्ट जवाब मांगा गया है। केजरीवाल ने कहा कि वह गुरुवार को पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर और स्थानीय मैकेनिकों से मिलकर आम उपभोक्ताओं का अनुभव जानेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता पर ई20 थोपना चाहती है और इस मुद्दे पर लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कभी इसे ट्रायल बता रही है और कभी इसे पूरी तरह सुरक्षित, जिससे सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

पहाड़गंज में रंगदारी और फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज में रंगदारी और फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी पवन कुमार उर्फ पवन पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पवन को सोमवार देर रात आईपी एस्टेट के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हुए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। गोलीबारी के दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे पकड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि जांच से पता चला है कि रंगदारी और फायरिंग की यह घटना एक सोची-समझी आपराधिक साजिश का नतीजा थी, जिसमें स्थानीय मददगारों के साथ मिलकर काम करने वाला एक अंतरराज्यीय गिरोह शामिल था।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया में युवती से छेड़खानी, बिजली विभाग के जेई समेत चार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

वेब वार्ता, देवरिया। देवरिया जिले के देवरिया शहर के कैलाशपुरी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने बिजली विभाग के जेई समेत चार नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार युवती का आरोप है कि उसकी सहेली ने उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां पहले से मौजूद युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में विजली विभाग का जेई भी शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़िता के अनुसार, तीन जुलाई की रात करीब आठ बजे उसकी सहेली ने उसे आइटीआइ के पास स्थित बड़ी सब्जी मंडी में बुलाया। वहां सहेली के साथ जेई शैलेश गौतम तथा अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने उसे जबरन बिजली विभाग के आवास परिसर के पास ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वहां शराब पी जा रही थी और उसके साथ अशोभनीय हरकत करते हुए छेड़छाड़ की गई। किसी तरह कमरे से निकलकर उसने डायल-112 पुलिस की मदद ली, जिसके बाद उसकी जान बच गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना की शिकायत लेकर जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची तो नीरज पांडेय, उसके पिता तथा अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित शैलेश गौतम, नीरज पांडेय, नीरज के पिता तथा बिजली विभाग के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 352 और 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चोरी की बड़ी वारदात, तीसरे घर में परिजन जागे तो भागे चोर

हरदोई। कोतवाली कछौना क्षेत्र के ग्राम मतुआ में मंगलवार की रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक तीन घरों को निशाना बनाया। दो घरों से नकदी और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए, जबकि तीसरे घर में परिजनों के जाग जाने से चोर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके और मौके से भाग निकले।

जानकारी के अनुसार, ग्राम मतुआ निवासी इरफान के घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए। वहां से सोने का हार, झूमर, मांगटीका, अंगूठी, झाला, पायल सहित लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इसके बाद बदमाश विमलेश सक्सेना के घर की छत के रास्ते अंदर पहुंचे और 36 हजार रुपये की नकदी के अलावा झुमकी, मंगलसूत्र, झाला, पायल तथा अन्य कीमती आभूषण समेट ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने पप्पू कश्यप के घर में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन आहट मिलने पर परिजन जाग गए। शोर-शराबा होते ही चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना कोतवाली कछौना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवारों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

चोरी की घटनाओं के बाद बागपत एसपी ने थाना प्रभारियों को बदला

बागपत, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की पुलिस व्यवस्था में मंगलवार रात बड़ा बदलाव हुआ है। एसपी सूरज कुमार राय ने कई थाना प्रभारियों के तबादले कर नई जिम्मेदारियां सौंपीं है। यह फेरबदल उस समय किए गए हैं जब जिले में चोरी की घटनाओं ने आम जनता को परेशान कर दिया । नलकूपों पर आए दिन चोरी, बिजली के खम्बों से विधुत लाइन चोरी की घटनाएं हुई है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने कई थानों की कमान बदल दी है जिससे पुलिसिंग के तरीके में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सबसे अहम बदलाव बागपत कोतवाली में हुआ, जहां प्रभारी बृजेश कुमार को साइबर थाना भेजते हुए उनकी जगह मनोज कुमार चहल को नई जिम्मेदारी दी गई।

पुलिस लाइन में प्रतीक्षारत 6 दरोगाओं को मिली थानों में तैनाती

फरुर्खाबाद, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के फरुर्खाबाद जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने मंगलवार को देर रात उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह राठौर को पुलिस लाइन से प्रभारी मीडिया सेल, कासिफ हनीफ को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सिविल लाइन (कोतवाली फतेहगढ़), संजय कुमार दुबे को पुलिस लाइन से थाना कादरीगेट, गौरव कुमार शुक्ल को पुलिस लाइन से थाना राजेपुर तथा अरविन्द कुमार को पुलिस लाइन से थाना कायमगंज भेजा गया है। वहीं, उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह को थाना मऊदरवाजा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा आरक्षी अरविन्द सिंह को सीसीटीएनएस कार्यालय से सर्विलांस सेल में तैनाती दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

विंध्य के विकास पर मुख्यमंत्री सख्त

मीरजापुर में समीक्षा बैठक कर अफसरों को तय समय में योजनाएं पूरी करने के दिए निर्देश

मीरजापुर, वेब वार्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मीरजापुर में अष्टभुजा स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी प्रस्ताव तय समयसीमा के भीतर शासन को भेजे जाएं।

बैठक में मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही जनपदों से जुड़े ग्राम सड़क, प्रमुख जिला मार्ग, सेतु निर्माण, बाईपास, धार्मिक पर्यटन और अन्य विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं तथा 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराने और जिलाधिकारियों को उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ समय पर जनता तक पहुंचना चाहिए। समीक्षा के दौरान मीरजापुर की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, मतवार मार्ग की मरम्मत तथा आवश्यक स्थानों पर इंटरलॉकिंग कराने के निर्देश दिए गए। वन भूमि से जुड़े मामलों में शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और कालीखोह मंदिर को जोड़ने वाले मार्गों की साफ-सफाई, सुंदरीकरण, अतिक्रमण हटाने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विंध्यधाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में नटवां रेलवे अंडरपास में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आषाढ़ में 'शिक्षा परिवार' पर की 'समृद्धि की बारिश'

वाराणसी, वेब वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आषाढ़ मास में बाबा विश्वनाथ की धरा से उत्तर प्रदेश के ह्यशिक्षा परिवारह्न पर ह्यसमृद्धि की बारिशह्न की। उन्होंने शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, उनके आश्रितों, बच्चों, संविदा कर्मियों आदि को बड़ी सौगात दी। सीएम ने इसके साथ ही शिक्षकों से अपील की कि आप अनुशासित वातावरण बनाकर बच्चों को मेहनत व प्यार से पढ़ाकर गढ़िए। देश का भविष्य अच्छा होगा तो हर नागरिक का भविष्य अच्छा हो जाएगा। स्कूल का वातावरण स्वच्छ, सुंदर, अनुशासित और आध्यात्मिक तेज से परिपूर्ण दिखे। आप बच्चों का ध्यान दें, सरकार आपका ध्यान रखेगी। हर बच्चा स्कूल जाए, यह नागरिकों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों का दायित्व है। सीएम ने सरकार के अन्य विभागों व निजी क्षेत्र से भी अपने कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने को कहा। सीएम योगी ने बुधवार को 12 लाख शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 1.10 करोड़ विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग, स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में कुल 1320 करोड़ की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों व संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू भी किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश भर में 404 स्थानों पर आयोजित किया गया।

ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने से किशोर की मौत

वेब वार्ता, देवरिया। जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के सिंगही में ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। किशोर अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर थानाध्यक्ष सुरौली व बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पंहुच कर घटना की जानकारी ली।

सुरौली थाना क्षेत्र के सिंगही निवासी गिरीश चौहान का एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। उनका पुत्र किशन (16) नौवीं कक्षा का छात्र था। बुधवार की सुबह वह घर से निकलकर गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा ई रिक्शा चार्जिंग में लगाया गया था। चार्जिंग में लगाया गए तार में कहीं कट था जिसके संपर्क में किशन आ गया और उसे करंट का तेज झटका लग गया। झटका लगते ही दूर जा कर सिर के बल गिरा और और सिर फट गया। मौके पर मौजूद लोग आनन-फानन में उसे देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

काशीवासियों के लिए विशेष इंतजाम, अगल द्वार से होंगे दर्शन

बंद रहेंगे वीआईपी और स्पर्श दर्शन, निरस्त रहेंगे सारे प्रोटोकॉल

वाराणसी, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। श्रावण मास में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच काशीवासियों को बड़ी राहत दी गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए अलग दर्शन व्यवस्था की है। काशीवासी गेट नंबर 4इ से अपना पहचान पत्र दिखाकर बिना सामान्य भीड़ में लगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वीआईपी और स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सभी तरह के प्रोटोकॉल भी निरस्त रहेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, ओआरएस, ग्लूकोज आदि की व्यवस्था रहेगी।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि काशीवासी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य वैध पहचान पत्र दिखाकर इस विशेष प्रवेश द्वार से सीधे बाबा के सुगम दर्शन कर सकेंगे। गेट नंबर 4इ से लेकर मंदिर तक स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें सामान्य भीड़ और धक्का-मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंदिर प्रशासन के इस निर्णय का काशीवासियों ने स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उन्हें अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ के दर्शन पहले की तुलना में अधिक सहज और सुविधाजनक तरीके से मिल सकेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि श्रावण मास के लिए पहले से निर्धारित एसओपी को पूरी तरह लागू किया जाएगा। धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सात प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथ ही नगर निगम से प्रवेश और निकास द्वारों के पास जूता-चप्पल रखने की अतिरिक्त व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सावन के दौरान सभी प्रकार के प्रोटोकॉल समाप्त रहेंगे और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। इसके अलावा स्पर्श दर्शन पर भी रोक रहेगी। यदि श्रद्धालुओं की भीड़ कम रहती है तो मंदिर न्यास इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सकता है। विश्वभूषण मिश्र ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे खाली पेट दर्शन के लिए कतार में न लगें। धाम प्रशासन की ओर से ग्लूकोज, ओआरएस और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि श्रद्धालु मोबाइल, चाबी, पेन तथा अन्य धातु की वस्तुएं अपने ठहरने के स्थान पर ही छोड़कर आएं, क्योंकि सावन में लगेज काउंटर पर अत्यधिक दबाव रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मिला नया संबल, हरदोई में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 8 जुलाई। शिक्षा केवल समाज का भविष्य नहीं गढ़ती, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी होती है। इसी भावना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना एवं डीबीटी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग दस लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी संपादित किया गया।

शासन के निर्देशानुसार हरदोई में पिहानी रोड स्थित जे.के. ग्रांड रिसॉर्ट में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में वाराणसी से प्रसारित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक इस अवसर के साक्षी बने।

समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज के कल्याण के लिए शुरू की गई यह योजना सरकार की

संवेदनशील सोच का परिचायक है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों एवं उनके परिवारों को बेहतर और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा कैशलेस व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीते नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आज दिखाई दे रहा है।

कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के दस-दस शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किए गए। अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये तथा उनके पात्र आश्रित सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आधार आधारित ई-केवाईसी तथा डिजिटल चिकित्सा कार्ड की व्यवस्था भी की गई है।

कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं एजुकेट गर्ल्स और प्रथम द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी गई। आयोजन की सफलता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों, एसआरजी, एमआईएस टीम तथा कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

देवरिया में 1.07 लाख किसानों की फार्मर आईडी लंबित

आधार-खतौनी में नाम की गड़बड़ी प्रमुख बाधा बनी

देवरिया 8 जुलाई। देवरिया जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद करीब 1.07 लाख किसान अब भी इससे वंचित हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आधार कार्ड और खतौनी में नाम का अलग-अलग दर्ज होना तथा तहसील स्तर पर अंश निर्धारण की प्रक्रिया पूरी न होना है। इससे किसानों को भविष्य में किसान सम्मान निधि, खाद-बीज समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। देवरिया जिले के 5,36,854 किसानों की फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए 1915 गांवों में कई बार विशेष शिविर लगाए गए।

कृषि विभाग के अनुसार, अब तक 4.29,512 किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। लेकिन करीब 1.07 लाख किसानों का पंजीकरण अभी अधूरा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में किसानों के आधार कार्ड और खतौनी में नाम या अन्य विवरण अलग-अलग होने से सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

कई मामलों में तहसीलों से अंश निर्धारण लंबित होने के कारण भी फार्मर आईडी जारी नहीं हो सकी है। कुछ किसान रोजगार के सिलसिले में बाहर होने के कारण भी पंजीकरण नहीं करा पाए हैं।फार्मर आईडी बनाने में लापरवाही को लेकर पहले कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो सका है।

इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन से निर्देश मिलने पर गांव-गांव फिर से विशेष शिविर लगाकर शेष किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। साथ ही जो किसान वर्तमान में आवेदन कर रहे हैं, उनका पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

फार्मर आईडी भविष्य में किसान सम्मान निधि, सरकारी गोदामों से खाद-बीज वितरण समेत कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बनती जा रही है। ऐसे में जिन किसानों की आईडी नहीं बन पा रही है, उन्हें जल्द से जल्द आधार और खतौनी के विवरण में सुधार कराने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में सुभाष मौर्य उप कृषि निदेशक देवरिया ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए गांवों में कर्मचारी पहुंच रहे हैं। जो लोग गांव में नहीं है उन्हीं का अधिकांश फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सका है। इसके लिए किसानों से मोबाइल पर कर्मचारी संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री करा रहे हैं।

फोरलेन पर खड़ी बरात की बस में ट्रक ने मारी टक्कर, दो लोगों की हालत गंभीर

कुशीनगर 8 जुलाई। कुशीनगर जिले में बरातियों से भरी व फोरलेन पर खड़ी बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस चालक व बराती समेत दो लोग घायल हो गए। मंगलवार की रात दस बजे सुकरौली कस्बे में फोरलेन पर हुई दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई।

आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना बाद ट्रक चालक फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार अनुसार गोरखपुर के चिलुआताल थाने के डोहरिया गांव के उमेश निषाद के पुत्र विद्यार्थी की बरात कप्तानगंज जा रही थी। बरातियों से भरी बस का पिछला पहिया सुकरौली कस्बे में पंक्चर हो गया। चालक सुरेंद्र निवासी शाहपुर थाना इटवा जिला सिद्धार्थनगर ने बस रोकी। नजदीक स्थित पंक्चर बनाने वाले दुकानदार से बात की।

दुकानदार जैसे ही पहिया खोलने पहुंचा कि गोरखपुर की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। इससे 45 वर्ष के चालक व बगल में खड़े 20 वर्ष के बराती अंश निषाद निवासी डोहरिया घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली ले जाया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक की पहचान कर ली गई है। शीघ्र ही चालक को पकड़ लिया जाएगा।

अदालती आदेश के अनुपालन पर उठे सवाल

एसडीएम बिलग्राम को कानूनी नोटिस

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जनपद हरदोई की बिलग्राम तहसील के ग्राम श्यामपुर मल्लावां निवासी दिवाकर मिश्रा ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलग्राम को सात दिन का कानूनी नोटिस भेजते हुए आरोप लगाया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अब तक पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित की गई है।

कानूनी नोटिस के अनुसार, वाद संख्या 6467/2024 में उपजिलाधिकारी न्यायालय, बिलग्राम ने 23 जनवरी 2025 को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। दिवाकर मिश्रा का आरोप है कि आदेश पारित होने के लंबे समय बाद भी उसके अनुपालन की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि कथित अवैध कब्जे को हटाने तथा न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने अपेक्षित कदम नहीं उठाए।

सीईआईआर पोर्टल की मदद से हरदोई पुलिस का बड़ा अभियान, 167 गुम मोबाइल स्वामियों को सौंपे

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। हरदोई पुलिस ने सर्विलांस सेल एवं केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की सहायता से गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बीते पांच माह के दौरान पुलिस ने 167 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद भर में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सर्विलांस सेल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों और सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर तकनीकी

विश्लेषण करते हुए 167 मोबाइल फोन बरामद किए। मंगलवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने सर्विलांस सेल द्वारा बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए। लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने हरदोई पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। मोबाइल बरामदगी अभियान में सर्विलांस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक अब्दुल जब्बार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक आकाश कुमार तथा आरक्षी राजकुमार वर्मा, ओमवीर सिंह, नितिन कुमार गुप्ता और यादवेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सीईआईआर पोर्टल के प्रभावी उपयोग से गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी की संभावना बढ़ी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल संबंधित थाने में सूचना देने के साथ ही सीईआईआर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

महत्वपूर्ण ख़बर

पिघलती बर्फ : महाविनाश की आहट और वैश्विक जलवायु संकट

■ लंदन। अंटार्कटिका महाद्वीप भले ही हमसे हजारों मील दूर हो, लेकिन वहाँ हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक विनाशकारी अलार्म बजा रहे हैं। यूरोपियन जियोसाइंसेज यूनियन (ईजीयू) के एक नए शोध ने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का ग्लोबल वार्मिंग से गहरा संबंध है। हाल के एक सितंबर महीने में, अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने रिकॉर्ड स्तर से बहुत कम पाई गई है। इस क्षेत्र में तापमान सामान्य से 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो लगभग एक महीने तक लगातार बना रहा। फ्यूचर साइंस की रिपोर्ट के अनुसार, ऐतिहासिक औसत की तुलना में लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर समुद्री बर्फ गायब हो चुकी है। इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ का पिघलना धरती के जलवायु तंत्र में बड़े और खतरनाक बदलाव का स्पष्ट संकेत है, जिससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है।

तेल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, भारत को भारी मुनाफा

■ दुबई। खाड़ी का एक प्रमुख और आर्थिक रूप से सशक्त देश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक संगठन ओपेक से अलग होकर वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है। ओपेक की पाबंदियों और उत्पादन कोटे की बेड़ियों से मुक्त होते ही यूएई ने अपने कच्चे तेल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी बाढ़ आ गई है।

राम मंदिर दान चोरीः तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर, खुलेंगे कई राज

अयोध्या। राम मंदिर में दान चोरी के मामले में पुलिस को तीन आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है, जिससे इस प्रकरण से जुड़े कई नए राज खुलने की उम्मीद है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय नामक इन तीनों आरोपियों को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने अदालत से सात दिनों की रिमांड मांगी थी, यह दलील देते हुए कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और उनसे मिली जानकारियों के आधार पर नए साक्ष्यों एवं अन्य वस्तुओं की बरामदगी आवश्यक है। पुलिस अब इन आरोपियों से रुपयों को कहां-कहां खपाया गया, कैसे चुराया गया और कहां छिपाया गया, इन सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी।

यह मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और निदेर्शों के आधार पर ही दान चोरी के मामले में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, अदालत के निर्देश पर पुलिस ने इन आरोपियों से बारी-बारी से जेल में भी पूछताछ की थी। एक आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर एक कार समेत कई बरामदगी भी की जा चुकी है। अब तीन अन्य प्रमुख आरोपियों की रिमांड मिलने से जांच में और तेजी आने की उम्मीद है। मामले के विवेचक एवं सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने अदालत में मौजूद रहकर पुलिस की दलीलों को मजबूती से पेश किया, जबकि आरोपियों की ओर से नियुक्त डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने रिमांड अर्जी का विरोध किया। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए लगभग 40 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। बुधवार सुबह तीनों आरोपियों को जेल से पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। तीन दिन पहले, 5 जुलाई को, पुलिस ने अदालत की अनुमति से जेल में भी तीनों आरोपियों से करीब पांच घंटे तक गहन पूछताछ की थी। उस दौरान आरोपियों के मोबाइल चैट की जांच में कई नई जानकारियां सामने आईं, जिनका मौके पर ही सत्यापन भी कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी। अब कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर नए साक्ष्यों, डिजिटल सबूतों और अन्य संभावित बरामदगी की कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों व नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी

लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनी ढेर

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर जाकिर गनी को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ के चार दिन बाद घटनास्थल से उसका शव बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जाकिर गनी पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ा हुआ था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की तलाश में था।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान पहले गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थीं, जिसके

बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा गया और मंगलवार को तलाशी के दौरान एक शव बरामद हुआ। मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुष्टि हुई कि मारा गया आतंकी जाकिर गनी था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शोपियां जिला लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का

पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकी का चार दिन बाद मिला शव

संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। यह इलाका लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे संगठनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण कश्मीर को पीर पंजाल पर्वतमाला से जोड़ने वाला यह क्षेत्र घने सेब के बागानों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आतंकियों के लिए छिपने और आवाजाही का सुरक्षित मार्ग बनता रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में शोपियां में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, बाहरी मजदूरों तथा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विक्टर फोर्स सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं।

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जाकिर गनी के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि आतंकियों के किसी भी शेष नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामलाः मंदिर समिति के पीए निलंबित

देहरादून। बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पांच दिन बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने अध्यक्ष के पर्सनल सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच में चढ़ावा चोरी की पुष्टि होने के बाद की गई है, जिससे इस प्रकरण ने अब एक गंभीर सियासी रंग ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच समिति को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में एसआईटी जांच की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। निलंबित किए गए प्रमोद नौटियाल पर प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मंदिर समिति के अनुसार, नौटियाल वर्तमान में जिस पद पर हैं, उससे जांच प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते उन्हें 3 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब निलंबित कर दिया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया

ईवीएम बनाने में भी भारत करेगा मदद

नई दिल्ली। भारत-इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मुहर लग गई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला दूसरा देश बन गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विकसित करने में मदद करेगा। इंडोनेशिया दौरे का दूसरे दिन मंगलवार सुबह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें गले भी लगाया। पीएम मोदी दिन में इंडोनेशिया के मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा।

प्रौढ़ महिला को अपनी पसंद से रहने का पूरा अधिकार, माता-पिता या पुलिस नहीं कर सकते मजबूर- बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। प्रौढ़ महिला को अपनी इच्छा के अनुसार रहने, विवाह करने या न करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मायके लौटने के लिए न तो राज्य की कोई एजेंसी और न ही उसके माता-पिता मजबूर कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को 21 वर्षीय युवती के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की

खंडपीठ ने 2 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा कि संबंधित युवती हैदराबाद स्थित अपने माता-पिता के घर से अपनी स्वतंत्र इच्छा से निकली थी। चूंकि वह बालिग है, इसलिए उसे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह कहां रहेगी, शादी करेगी या नहीं करेगी तथा आगे की पढ़ाई करेगी या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस युवती को ह्यलापता व्यक्तिह्न मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती और न ही उसे जबरन उसके माता-पिता के पास वापस भेज सकती है। अदालत ने तेलंगाना पुलिस को निर्देश दिया कि युवती के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। युवती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका में बताया गया कि उसने जून 2026 में अपने दत्तक माता-पिता का घर छोड़ दिया था। उसका आरोप था कि परिवार उस पर अपने से लगभग दस वर्ष बड़े चचेरे भाई से विवाह करने का दबाव बना रहा था, जबकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसका परिवार अत्यधिक रूढ़िवादी और पारंपरिक सोच वाला है, जिसके कारण उसे स्नातक की पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। साथ ही, परिवार की ओर से मिल रही धमकियों और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी अदालत से की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युवती से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इस दौरान उसने अदालत को बताया कि वह वर्तमान में मुंबई में एक स्वयंसेवी संस्था के साथ कार्य कर रही है और पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि उसे मात्र दो महीने की उम्र में गोद लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान युवती की दत्तक मां ने अदालत में शपथपत्र दाखिल कर भरोसा दिलाया कि बेटी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और उसकी उच्च शिक्षा में भी कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बावजूद युवती ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। युवती की स्पष्ट इच्छा और उसके बालिग होने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार किसी भी प्रौढ़ महिला को अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने का अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अल्ट्रावायलेट तकनीक ने खोले करोडों वर्ष पुराने मगरमच्छ के रहस्य

मेंड्रिड। एक सदी से अधिक समय तक स्पेन के एक संग्रहालय में रखा रहा एक जीवाश्म आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की मदद से 12.5 करोड़ वर्ष पुराने मगरमच्छ से जुड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण साबित हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज प्राचीन मगरमच्छों के विकास, उनकी शारीरिक संरचना और जीवनशैली को समझने में नई दिशा दे सकती है। अल्ट्रावायलेट (यूवी) प्रकाश के उपयोग से वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म में त्वचा, रंगों के पैटर्न और नरम ऊतकों के ऐसे निशान खोजे हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देते। यह जीवाश्म स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र के नोगुएरा इलाके से वर्ष 1902 में भूवैज्ञानिक लुइस मारिया विडाल द्वारा चूना पत्थर की खदान से प्राप्त किया गया था।

गडकरी बोले- एक कार बता दो जो ई-20 पेट्रोल से खराब हुई हो

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथनॉल मिश्रित ई20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस ईंधन के इस्तेमाल से किसी भी वाहन में तकनीकी खराबी का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने आलोचकों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी कार में ई20 पेट्रोल की वजह से समस्या आई है तो उसका एक उदाहरण सामने रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर गलत जानकारियां फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। गडकरी के अनुसार भारत को आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि देश हर साल पेट्रोलियम ईंधन के आयात पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। उनका मानना है कि यह आर्थिक बोझ कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ई20 का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिली है। एथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और चावल जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है, जिससे किसानों को भी लाभ मिल रहा है।

गडकरी ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि उनके परिवार से जुड़ी कंपनियां एथनॉल उत्पादन के कारण इस नीति का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार की चीनी मिलें जरूर हैं, लेकिन वे एथनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देश में एथनॉल का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और मक्के से एथनॉल बनाने की नीति का सीधा फायदा किसानों को मिला है। उनके अनुसार इस कदम से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की आय में करीब 45 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले मक्के की बाजार कीमत लगभग 1,200 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,800 रुपये था। एथनॉल उत्पादन बढ़ने के बाद इसकी कीमत बढ़कर करीब 2,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे। केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार भविष्य में वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को और बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वाहन उत्सर्जन संबंधी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पहल के तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के साथ-साथ ई85, ई100, बी100 बायोडीजल और हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण जैसे स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता भी घटेगी।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव सिद्धार्थ यादव को भी पद से हटाया

पीएमओ तक पहुंचा मामला, सरकार ने कारणों पर साधी चुप्पी

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनके चार निजी सहयोगियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

हाल ही में अतिरिक्त निजी सचिव (एपीएस) सिद्धार्थ यादव को पद से हटाए जाने के साथ ही अब तक मंत्री कार्यालय से चार प्रमुख अधिकारियों की विदाई हो चुकी है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक भी पहुंच चुका है, हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, सिद्धार्थ यादव ने 1 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। इससे पहले निजी सचिव अमर सिंह तथा अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह और आयुष सरन को भी

उनके पदों से हटाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अमर सिंह, शैलेश कुमार सिंह और आयुष सरन उस समय से भूपेंद्र यादव के साथ जुड़े थे, जब वह श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। इनके स्थानांतरण और हटाए जाने संबंधी आदेश बाद में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए।

हालांकि केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों को हटाने के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक कुछ गंभीर शिकायतें पहुंची थीं। इन शिकायतों के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि संबंधित अधिकारियों का प्रभाव आवश्यकता से अधिक बढ़ गया था और उन पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप करने के आरोप लगे थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच मंगलवार को उन्होंने दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधे लगाने के अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया। ऐसे समय में उनके कार्यालय में हुए इस बड़े फेरबदल को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चचाओं का दौर जारी है।

भारत का बड़ा कदमः चाबहार-जहेदान रेल से मध्य एशिया का सीधा रास्ता

नई दिल्ली। भारत ने ईरान में 700 किलोमीटर लंबे रणनीतिक चाबहार-जहेदान रेल कॉरिडोर पर काम को पुन: सक्रिय करने की अपनी योजना को गति दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों, जैसे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तक भारत की पहुंच को सुगम बनाना है। यह रेल लाइन भारत के लिए क्षेत्र में एक नया व्यापारिक और रणनीतिक मार्ग खोलेगी, जिससे उसकी भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। यह परियोजना भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और पाकिस्तान में विकसित किए गए ग्वादर पोर्ट का एक प्रभावी जवाब माना जा रहा है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने और अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए, भारत चाबहार बंदरगाह और उससे जुड़े रेल लिंक को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देख रहा है। यह भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सीधे आर्थिक संबंध स्थापित करने का मौका प्रदान करेगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रस्तावित चाबहार-जहेदान रेल मार्ग ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित जहेदान से जोड़ेगा।

15 जुलाई से लागू होने जा रहा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा है। फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने यह घोषणा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और रोजगार के नए मौकों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए थे और अब इसके लागू होने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। समझौते के प्रभावी होने से पहले उद्योगों और कारोबारियों को नई व्यवस्था के अनुरूप अपने व्यापारिक ढांचे और रणनीतियों को तैयार करने का समय दिया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

एफटीए के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बड़ी राहत मिलने वाली है। ब्रिटेन भारतीय कपड़ा, फुटवियर, कृषि एवं खाद्य उत्पादों सहित कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी करेगा। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और उन्हें ब्रिटिश बाजार में अधिक अवसर मिलने है। विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए भी समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा।

ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय कुशल कर्मचारियों को दोहरे सोशल सिक्योरिटी योगदान से छूट की अवधि 36 महीने से बढ़ाकर 60 महीने कर दी गई है। इस बदलाव से भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों दोनों का वित्तीय बोझ कम होगा तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेशेवरों की आवाजाही आसान बनेगी।

दूसरी ओर, भारत ने भी ब्रिटिश उत्पादों के लिए अपने बाजार में अधिक पहुंच देने पर सहमति जाहिर की है। समझौते के तहत ब्रिटिश व्हिस्की पर आयात शुल्क में भारी कटौती की जाएगी। साथ ही निर्धारित कोटा व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर लगने वाले शुल्क को भी काफी कम करेगा। इससे ब्रिटिश कंपनियों को भारतीय बाजार में बेहतर अवसर मिलने और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, तकनीकी सहयोग, सेवा क्षेत्र और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उस समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था नए व्यापारिक साझेदारों और बाजारों की तलाश कर रही है, भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, इससे भारत के निर्यातकों को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि ब्रिटिश निवेशकों को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत में नए मौके प्राप्त होने है। यह समझौता आने वाले वर्षों में दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

उप मुख्यमंत्री साव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पोस्टर का किया विमोचन

रायपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जन-जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने योजना के तहत बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले प्रदेश के 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों में 12 हजार लोगों को कुल 240 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनी है। मात्र 436 रुपए के वार्षिक अंशदान वाली यह योजना परिवारों को कठिन परिस्थितियों में संबल और भविष्य के प्रति भरोसा देने का कार्य कर रही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ अमित झिंगरन, बिजनेस स्ट्रेटजी प्रेसीडेंट संतोष चाको, वेस्ट जोन के जोनल डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव और भोपाल रीजन (Region) के रीजनल डायरेक्टर अमित कुमार साहा भी मौजूद थे।

कलेक्टर गौरव सिंह ने ली समय सीमा की बैठक

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी नगरीय निकाय सहित जनपद पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करें और जल्द समाधान करें। समाज कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए समन्वय कर सभी हितग्राहियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्लांटेशन के लिए कार्ययोजना बनाएं इसके लिए उद्योग विभाग, वन विभाग समन्वय बनाकर सड़कों के किनारे पौधरोपण का कार्य करें। डॉ. सिंह ने कहा कि शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की समस्या को देखते हुए ई-रिक्शा की आवश्यकता है इसके लिए श्रम विभाग हितग्राहियों की सूची बनाकर वितरण कराएं। उन्होंने कहा कि जिन नगरीय निकायों एवं जनपद में प्रधानमंत्री आवास की जो किश्त लंबित है उसकी प्रक्रिया जल्द पूर्ण करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम श्री उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जनगणना कर्मियों को शीघ्र मानदेय, भुगतान के लिए कलेक्टरों को 58 करोड़ जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की पहल पर जनगणना 2027 के कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कल ही जनगणना निदेशक, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन प्रेषित कर विशेष अर्जित अवकाश प्रदान करने तथा लंबित मानदेय राशि का शीघ्र भुगतान की मांग की थी। इस पर त्वरित संज्ञान ले शासन द्वारा मानदेय भुगतान के लिए 58.60 करोड़ सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। जिससे शीघ्र ही जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लंबित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वहीं, विशेष अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने संबंधी मांग पर भी जनगणना संचालन निदेशक द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

एमसीबी : मोर गांव मोर पानी अभियान बना जल संरक्षण की नई मिसाल

350 आजीविका डबरियां और 150 से अधिक सामुदायिक तालाब बदलेंगे ग्रामीण जल परिदृश्य

रायपुर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिले में संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। अभियान के तहत जिले में 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया गया है। इन कार्यों से वर्षा जल के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिलने लगी है।

जिले में मानसून के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्मित इन जल संरचनाओं से अब जल संरक्षण के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आजीविका डबरियां एवं सामुदायिक तालाब वर्षा जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ खेतों में सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे किसानों को खेती के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा तथा फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

अभियान के अंतर्गत निर्मित 350 आजीविका डबरियां ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए अवसर भी सृजित करेंगी। इन डबरियों का उपयोग मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन तथा अन्य आजीविका गतिविधियों में किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं

150 से अधिक सामुदायिक तालाबों के निर्माण एवं गहरीकरण से गांवों में जल संचयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इन तालाबों से सिंचाई, पशुओं के लिए पेयजल, भू-जल पुनर्भरण तथा पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। गर्मी के मौसम में जल संकट से राहत मिलने के साथ-साथ जल स्रोतों की स्थिरता भी बनी रहेगी।

जिला प्रशासन द्वारा संचालित यह अभियान केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों तथा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। सामुदायिक सहयोग से निर्मित इन जल संरचनाओं का संरक्षण एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि इनके दीर्घकालिक लाभ ग्रामीणों को निरंतर मिलते रहें।

जिला प्रशासन का मानना है कि जल संरक्षण ही भविष्य की जल सुरक्षा का आधार है। इसी सोच के साथ मोर गांव मोर पानी अभियान के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण, भू-जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह अभियान जिले को जल समृद्ध, आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी ग्राम वासियों से अपील की है कि वे निर्मित आजीविका डबरियों एवं सामुदायिक तालाबों की सुरक्षा, स्वच्छता और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

खेती-किसानी को मिली रफ्तार, प्रमुख जलाशयों में 54.34 प्रतिशत जलभराव

अब तक 241.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज, सामान्य के बेहद करीब पहुँचा आंकड़ा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून अपनी सही लय में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर आज तक की स्थिति में प्रदेश में कुल 241.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि की औसत वर्षा (252.7 मिमी) का 95.6 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में मानसून की स्थिति पूरी तरह सामान्य और संतोषजनक बनी हुई है।

बलरामपुर और कोरबा में जमकर बरसे बदरा

दिनांक 6 जुलाई तक राज्य में औसतन 22.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। चौबीस घंटों के भीतर सबसे ज्यादा वर्षा बलरामपुर में 67.6 मिमी, कोरबा में 54.9 मिमी, रायपुर में 45.3 मिमी और सूरजपुर में 42.8 मिमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, बस्तर संभाग के सुकमा (0.4 मिमी) और दंतेवाड़ा (0.8 मिमी) में आज कम बारिश हुई।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सामान्य से दोगुनी बारिश, सुकमा अभी भी पीछे

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला 213.3 प्रतिशत वर्षा के साथ पूरे प्रदेश में सबसे आगे है, जहाँ अब तक 453.3 मिमी बारिश हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी रायपुर (136.9प्रतिशत), सक्ती (134.7प्रतिशत), दंतेवाड़ा (129.2प्रतिशत), दुर्ग (126.6प्रतिशत) और बलरामपुर (126.3प्रतिशत) में भी सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह बिलासपुर में 86.1प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 101प्रतिशत, बेमेतरा में 93.2प्रतिशत और नारायणपुर में 91.8 प्रतिशत सहित कई जिले में वर्षा संतोषजनक बने हुए हैं। सुकमा जिला 55.4 प्रतिशत वर्षा के साथ इस सूची में सबसे पीछे है। इसके साथ ही मोहला-मानपुर (63.3 प्रतिशत), गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (64.3 प्रतिशत) और सरगुजा (67.5 प्रतिशत) में फिलहाल बारिश सामान्य से थोड़ी कम है।राज्य के प्रमुख जलाशयों में दुधावा बांध 72.74 प्रतिशत, मनियारी जलाशय 76.97 प्रतिशत, खारंग जलाशय 67.10 प्रतिशत तथा सोंढूर जलाशय 65.89 प्रतिशत क्षमता के साथ बेहतर स्थिति में हैं। प्रदेश के सबसे बड़े मिनीमाता बांगो जलाशय का भी लाईव स्टोरेज अब 59.42 प्रतिशत हो गया है। वहीं रविशंकर सागर (गंगरेल) में 47.66 प्रतिशत, तांदुला में 43.93 प्रतिशत तथा सिकासार में 41.10 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। मध्यम जलाशयों की बात करें तो छिरपानी जलाशय 78.13 प्रतिशत, सूखा नाला बैराज 77.92 प्रतिशत, सुतियापाठ 73.28 प्रतिशत तथा पिपरिया नाला 70.19 प्रतिशत भरे हुए हैं। हालांकि कुछ जलाशयों में जलभराव अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिनमें परलकोट, कुम्हारी, केशवा और मयाना प्रमुख हैं।

प्रमुख बांधों में 56.63 तक पहुंचा लाइव स्टोरेज

प्रदेश में मानसून की सक्रियता का असर अब जलाशयों में साफ दिखाई देने लगा है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के प्रमुख और मध्यम सिंचाई जलाशयों में जलभराव की स्थिति में इजाफा हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 12 प्रमुख जलाशयों में कुल लाइव स्टोरेज 56.63 प्रतिशत तथा 34 मध्यम जलाशयों में 42.13 प्रतिशत है। फिलहाल कुल मिलाकर राज्य के प्रमुख एवं मध्यम जलाशयों में 54.34 प्रतिशत जल भंडारण उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी बेहतर है।

खेती-किसानी को मिली गति, बाढ़ नियंत्रण कक्ष अलर्ट पर

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी के अनुसार, प्रदेश भर में बारिश की स्थिति और नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में हो रही यह बारिश राज्य के किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है, जिससे खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई के कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है।

पीएम आवास योजना से पात्र परिवार न छूटे शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र

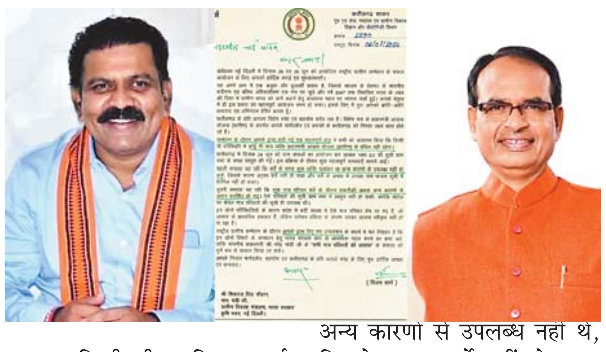

रायपुर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है।

पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पत्र में दिल्ली में 28 और 29 जून को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हुए सम्मेलन के दौरान दिए गए उस आश्वासन का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 24 जून को ग्राम सभाओं के माध्यम से आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई। इस प्रक्रिया के दौरान दो प्रमुख समस्याएं सामने आईं। पहली, सर्वेक्षण के समय कई पात्र लोग पलायन या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे, जिससे उनका सर्वे नहीं हो सका और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया। दूसरी, कुछ पात्र परिवार तकनीकी अथवा अन्य कारणों से पोर्टल पर अपात्र प्रदर्शित हो गए, जिसके कारण उनकी जानकारी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों कारणों से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार योजना से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय और व्यवस्था की जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को आवास के संकल्प को पूरी तरह साकार किया जा सके। पत्र में विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन, सहयोग और छत्तीसगढ़ के प्रति उनके विशेष स्नेह के लिए आभार भी व्यक्त किया।

सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम ने दिवंगत साथियों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम द्वारा दिवंगत साथियों की स्मृति में 2 जुलाई संध्या 5बजे से वृन्दावन हॉल में भजन संध्या आयोजित की गयी थी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथी प्रदीप श्रीवास्तव (से.निवृत्त उप संचालक दूर दर्शन),विशिष्ट अतिथि मनमथ शर्मा तथा अजय काले अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडल उपस्थित हुये,कार्यक्रम की अध्यक्षता फोरम के डॉ. चितरंजन कर ने की हल्की बारिश के कारण कार्यक्रम की शुरूवात में थोड़ा विलम्ब हुआ। मां सरस्वती पूजन अतिथियों ,फोरम सदस्यों द्वारा किया। सरस्वती वंदना सुरिली मधुर आवाज में मैडम किरण पिल्लै ने गाया। कार्यक्रम के अतिथियों ने श्रद्धांजली भाषण दिया। फोरम अध्यक्ष प्रकाश सुरावधनीवार ने दिवंगत साथियों के द्वारा फोरम के लिये किये गये योगदान की याद दिलाई प्रशंसा की। भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुवात डॉ. चितरंजन कर द्वारा गाये सुमधुर गीतों से हुई, सुभाष वर्मा, मनोहर ठाकुर घनश्याम शर्मा, राजकुमार शुक्ला सचिव के अलावा

श्रीमती शीलू पटनायक, श्रीमती किरण पिल्ले, राजेन्द्र शर्मा ने बहुत सुन्दर कर्ण प्रिय भजनों की प्रस्तुती से सभागार में उपस्थित श्रोताओं को भक्तिभाव में बांधकर वाह वाही की तालियां बटोरी, दिवंगत सदसयों के परिवार जनों ने भी फोरम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार शुक्ला फोरम सचिव ने किया। दिवंगत साथियों को दो मिनट मौन श्रद्धांजली पश्चात, सचिव राजकुमार शुक्ला ने सभी लोगों को भोजन हेतु भोजन कक्ष में आमंत्रित किया। श्रीमती सरोज सैफी उपाध्यक्ष, एचएन राणा,कोषाध्यक्ष पीके चटर्जी, नितीश श्रीवास्तव, राकेश खरे कामले, सभी कार्यकारिणी के साथियों ने एक जुटता के साथ भजन संध्या के कार्यक्रम को सौहार्द्रपूर्ण, शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में भरपूर योगदान किया धन्यवाद

मुख्य सचिव ने सचिवों की ली उच्च स्तरीय बैठक

महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के लिए भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों

की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है।ुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक मे ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

वन विभाग में अब ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य

रायपुर. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल तथा सभी फील्ड कार्यालयों में कार्यालयीन फाइलों और डाक का संचालन अब अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा। मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा सभी कार्यों की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। इससे अनावश्यक विलंब कम होगा और आम नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है।

स्टॉक, पीओएस और विक्रय रिकॉर्ड में मिली विसंगतियां, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई

उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

रायपुर. खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है।

बेमेतरा जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रनबोड़ स्थित मेसर्स महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण, विक्रय या उर्वरक व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेगा।

कृषि विभाग के अनुसार संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्सन, अधिक कीमत पर बिक्री तथा

नकली और अमानक उर्वरकों की रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जून को नवागढ़ विकासखंड के रनबोड़ स्थित महालक्ष्मी कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के कई प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।

जांच के दौरान कैश मेमो पर किसानों के हस्ताक्षर नहीं मिले। भंडारण एवं विक्रय पंजी का संधारण अपूर्ण पाया गया, निर्धारित प्रारूप में मासिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा बिक्री स्थल पर उर्वरकों का स्टॉक और निर्धारित विक्रय दर भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में अन्य जिलों के किसानों को उर्वरक बेचे गए। इसके अलावा पीओएस सिस्टम में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में भी अंतर पाया गया।

इन अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन विभाग को दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं सह प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ की अनुशंसा पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ब्रह्मपुर-उधना -ब्रह्मपुर के अमृत भारत स्पेशल ट्रेन अब प्रतिदिन

रायपुर। 19021/19022 ब्रह्मपुरङ्कउधना -ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात के यात्रियों को सीधी एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक एलएचबी कोचों से सुसज्जित है। 19021/19022 ब्रह्मपुर-उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस को हफ्ते में 03 दिन चलने का निर्णय लिया गया था अब यह गाड़ी प्रतिदिन चलेगी। 19021 उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस उधना स्टेशन से 9 जुलाई, से एवं 19022 ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस ब्रह्मपुर स्टेशन से 10 जुलाई, से प्रतिदिन चलेगी। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 18251/18252 तथा 18249/18250 रायपुर-कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में 01अतिरिक्त एसी थ्री कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा रायपुर से 18251 रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस में 12 जुलाई से तथा 18252 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में 13 जुलाई से उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार रायपुर से 18249 रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस में 15 जुलाई से तथा 18250 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में 16 जुलाई से उपलब्ध रहेगी ।

महत्वपूर्ण ख़बर

जिम्बाब्वे दौरे में बेहतर प्रदर्शन कर अपने को साबित करना रहेगा युवा गेंदबाज अशोक का लक्ष्य

- मुम्बई। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का यहां तक का सफर आसान नहीं रहा है। राजस्थान के जयपुर के छोटे से गांव रामपुरा से निकलकर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले अशोक की खासियत उनकी गेंदबाजी की रफ्तार रही है। जिसके कारण वह अन्य प्रतियोगियों से आगे निकले। आईपीएल 2026 में 23 साल के अशोक ने 154.2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सभी को प्रभावित किया था। अशोक का लक्ष्य अब दौरे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाना है।

सूर्यकुमार ने भारतीय टीम के प्रति समर्थन जताया, वैभव को दी शुभकामनाएं

मुम्बई। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

भारतीय टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूर्यकुमार ने टीम के प्रति भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि वह बेहतर प्रदर्शन की कामना करते हैं। सूर्यकुमार ने 15 साल की उम्र में वैभव के डेब्यू को लेकर कहा कि ये तो उसे शानदार सफर की शुरूआत है। अभी उसे काफी आगे जाना है। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टी20 मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वैभव के लिए सूर्यकुमार ने लिखा, वैभव, यह तुम्हारे बेहद रोमांचक सफर की सिर्फ शुरूआत है। हर पल का आनंद लो और देश का नाम रोशन करते रहो। सूर्या का यह संदेश एक अनुभवी खिलाड़ी द्वारा एक युवा प्रतिभा को दिया गया महत्वपूर्ण प्रोत्साहन माना जा रहा है है।

सूर्यकुमार ने मौजूदा भारतीय टीम के लिए भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे और टीम को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे। उन्होंने लिखा, मैं टीम के लिए बेहद खुश हूं। मैं हमेशा खिलाड़ियों के लिए सिर्फ शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है कि सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मेरा पूरा समर्थन हमेशा मिलेगा।

यह संदेश ऐसे समय में आया है जब सूर्यकुमार को भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में, बीसीसीआई ने उनसे कप्तानी भी वापस ले ली थी और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंप दी। आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए घोषित टी20 टीम में भी सूर्यकुमार को जगह नहीं मिली है, जिससे उनके करियर पर सवालिया निशान लग गए हैं। खराब फॉर्म ही उनके बाहर होने की मुख्य वजह मानी जा रही है। इसी साल भारत को टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान होने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार संघर्ष और हालिया आईपीएल में मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उन्हें टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी है।

मेरी पहली प्राथमिता ऑस्ट्रेलियाई टीम से खेलना : कमिंस

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता ऑस्ट्रेलियाई टीम से खेलना है। ऐसे में साल 2027 में एकदिवसीय विश्वकप कप और एशेज सीरीज को देखते हुए वह आईपीएल से दूरी बना सकते हैं। कमिंस के अनुसार वह टेस्ट मैच और एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए उनकी लिए फिटनेस बनाये रखना जरुरी है। ऐसे में वह कार्यभार प्रबंधन को सबसे ज्यादा जरुरी मानने है। वहीं आईपीएल में खेलने से थकान ओर चोटिल होने का खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि अगले एक साल में 21 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, जिसमें आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने का अवसर भी रहेगा। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह व्यस्त कार्यक्रम 2027 में एकदिवसीय विश्व कप के साथ समाप्त होगा। वहीं मार्च में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 150वीं वर्षगांठ का टेस्ट मैच भी होगा। इसी बीच आईपीएल भी पड़ेगा। इसके बाद इंग्लैंड में एशेज सीरीज खेली जाएगी। कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज को जीतना चाहते हैं। इसका कारण है कि टीम ने साल 2001 के बाद से ही कोई सीरीज नहीं जीती है। कमिंस ने कहा कि फिटनेस बनाये रखने के लिए न किसी स्तर पर कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा और वह टेस्ट मैच या एकदिवसीय विश्व कप तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साथ ही कहा, मैं समय आने पर ही फैसला लूंगा और आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर देखूंगा कि क्या सही रहेगा। हालात बदल सकते हैं। मुझे कुछ चोटें भी लगी हैं, इसलिए मैं अभी कुछ भी पक्का नहीं कह चाहता।

सैमसन इन कारणों से टीम इंडिया से बाहर हुए

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका करियर संजू सैमसन जितना उतार-चढ़ाव भरा रहा हो। हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले सैमसन को अब टीम में अपनी जगह बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी उन्हें टी20 टीम में जगह नहीं मिली है। जिससे प्रशंसक हैरान हैं। इससे ये सवाल उठने लाजिमी हैं कि ऐसा क्या हुआ कि विश्व कप हीरो अचानक ही चयनकताओं की प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया है।

तीन महीने पहले ही विश्व कप में अपनी निडर और मैच विजेता पारियों से टीम को मजबूत करने वाले सैमसन का बल्ला उसके बाद से खामोश है। आयरलैंड दौरे पर भी वह रन बनाने में सफल रहे। अच्छी शुरूआत को वे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और स्ट्राइक रोटेट करने में भी संघर्ष करते दिखे। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर पहले टी20 में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दूसरे मैच में युवा वैभव सूर्यवंशी के लिए

प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ा। किसी भी खिलाड़ी के लिए बेंच पर बैठना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, और अब जिम्बाब्वे सीरीज से पूरी तरह बाहर होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चयनकताओं की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं।

सैमसन के करियर पर मंडराते इस संकट के पीछे तीन प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। पहला, उनका फॉर्म। विश्व कप की शानदार लय को वे बरकरार नहीं रख पाए। आयरलैंड और इंग्लैंड में छोटी पारियां उनके खिलाफ गईं, जो टी20 क्रिकेट में चयन पर सीधा असर डालती हैं। दूसरा, टीम इंडिया में विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारतीय टीम में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन से शीर्ष क्रम में कई विकल्प पेश कर रहे हैं। तीसरा कारण टीम प्रबंधन की भविष्य की योजनाएं। 31 वर्षीय सैमसन की उम्र को देखते हुए, टीम प्रबंधन शायद अब युवा खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि इसी कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए चयनकताओं ने अनभवी खिलाड़ियों की जगह पर युवाओं को प्राथमिकता दी है।

अमेरिका में तेजी से बढ़ रही क्रिकेट की लोकप्रियता : रिपोर्ट

न्यूयार्क। अमेरिका में अब क्रिकेट की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) रहा है। एमएलसी का चौथा सीजन भी चल रह है जिससे दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से देश में नए स्टेडियमों का निर्माण हो रहा है उससे भी खेल के बढ़ते रुझान का अंदाजा होता हे। इसके साथ ही साल 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किये जाने से भी इसका आकर्षण बढ़ा है। इससे साफ है कि अमेरकी धरती पर क्रिकेट धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है।

एमएलसी लीग में अभी छह टीमें खिताब के लिए उतरी हैं। अगले सत्र तक इसमें आठ टीमों को शामिल करने कीयोजना है, जो देश में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का एक स्पष्ट संकेत है। इस लीग ने न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि इसने अंतरराष्ट्रीय सितारों को भी अमेरिकी मैदानों पर आकर्षित किया है, जिससे दर्शकों की रुचि बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी इस खेल के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जब ओलंपिक में क्रिकेट मैचों के बाद अमेरिका के स्थानीय लोग भी इसे गंभीरता से अपनाएंगे। इससे खेल को एक नई पहचान मिलेगी और इसकी लोकप्रियता में तेजी आएगी। यह उम्मीद की जा रही है कि ओलंपिक मंच क्रिकेट को एक वैश्विक दर्शक वर्ग प्रदान करेगा और अमेरिकी युवाओं को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।

एमएलसी में कई बेहतरीन क्रिकेटर खेल रहे हैं। भारत को 2012 अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद साल 2021 से ही अमेरिका में क्रिकेट

खेल रहे हैं, ने पिछले पांच वर्षों में यहां खेल के तेजी से विकास को देखा है। उनका कहना है कि हर साल कुछ नया देखने को मिल रहा है। हाल ही में लॉस एंजिलिस में एक क्रिकेट स्टेडियम का तैयार होना इस विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। एलए नाइट राइडर्स ने कैलिफोर्निया के पोमोना में इस नए अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जिसमें आठ पिच, आईसीसी मानकों के अनुरूप आउटफील्ड और 120 फीट ऊंचे छह फ्लडलाइट टावर शामिल हैं। यही मैदान 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी करेगा, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है।

मेजर लीग क्रिकेट में दुनिया भर के कई बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें रविचंद्रन अश्विन, फाफ डु प्लेसिस, केशव महाराज, सुनील नारायण, मार्कस स्टोइनिस, कुसल परेरा, रचिन रवींद्र, हारिस रऊफ, उन्मुक्त चंद और जेसन होल्डर जैसे नाम शामिल हैं। इन सितारों की उपस्थिति लीग को वैश्विक पहचान दिला रही है। हालांकि, हरमीत सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि अमेरिका में क्रिकेट की स्थायी सफलता के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। उनके अनुसार, अभी देश में केवल तीन-चार प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम हैं, और अधिक शहरों में मैदान, प्रशिक्षण केंद्र तथा बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्कूल और कॉलेज क्रिकेट खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देना शुरू करेंगे और बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने का एक स्पष्ट मार्ग बनेगा, तभी अमेरिका में क्रिकेट की सच्ची और मजबूत नींव तैयार हो पाएगी।

मौजूदा मेजर लीग क्रिकेट सीजन 18 जून को शुरू हुआ था, जिसमें छह टीमें कैलिफोर्निया और टेक्सास के तीन मैदानों पर कुल 34 मुकाबले खेल रही हैं। इस रोमांचक टूर्नामेंट का फाइनल 18 जुलाई को कैलिफोर्निया के ओकलैंड कोलिजीयम में खेला जाएगा। यह सब अमेरिका में क्रिकेट के एक नए युग की शुरूआत का संकेत है, जहां यह खेल धीरे-धीरे अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और ओलंपिक की उम्मीदों से इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

कारोबार

चालू माह में मिल रही अल्ट्रोज और टियागो पर विशेष छूट

नई दिल्ली। जुलाई महीने में टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक अल्ट्रोज और टियागो पर आकर्षक छूट की घोषणा की है। अल्ट्रोज के रेसर वैरिएंट पर सबसे अधिक 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। इसके पेट्रोल और डीजल वैरिएंट्स पर 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है।

वहीं, अल्ट्रोज सीएनजी मॉडल पर इन छूटों के साथ 20,000 रुपये का इंटरवेंशन ऑफर भी दिया जा रहा है। अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमतें 6.3 लाख रुपये से 10.65 लाख रुपये के बीच हैं, और यह कई इंजन विकल्पों व उन्नत सुरक्षा फीचर्स जैसे 6 एयरबैग और ईएससी के साथ आती है। दूसरी ओर, टाटा मोटर्स प्री-फेसलिफ्ट टियागो के बचे हुए स्टॉक पर 35,000 रुपये तक की छूट दे रही है। एक्सई वैरिएंट को छोड़कर, टियागो के पेट्रोल और सीएनजी दोनों मॉडल्स पर 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपये

का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

कंपनी ने हाल ही में नई 2026 टियागो भी लॉन्च की है, जिसकी शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये से है। इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल (86एचपी) और सीएनजी (75.5 एचपी) इंजन विकल्प दिए गए हैं, जो मैनुअल और एएमटी यूनिट के साथ उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि 2026 टियागो सीएनजी एएमटी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो अपने सेगमेंट में पहली बार है। नई 2026 टियागो में शार्प हेडलैंप्स, एक नई ग्रिल और कनेक्टेड टेल-लैंप जैसे डिजाइन अपडेट मिलते हैं।

सोने और चांदी के भावों में आई नरमी

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को नरमी आई है। कीमती धातुओं में ये गिरावट डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले निवेशकों की सतर्कता से आई है। इससे सोने-चांदी की कीमतें गिरी हैं। दुनिया भर के साथ ही घरेलू बाजारों में भी कीमतें नीचे आयी हैं। आज कॉमेक्स पर सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस से नीचे आया। वहीं चांदी भी 60 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक खिसकी। घरेलू मार्केट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी फिसला है। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव 1,44,950 रुपये, जबकि चांदी के भाव 2,29,300 रुपये के करीब रहे। आज सोने के वायदा भाव की शुरूआत में भी कमी आई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त अनुबंध 192 रुपये की गिरावट के साथ ही 1,45,200 रुपये के भाव पर खुला जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,45,392 रुपये था। सोने के वायदा भाव इस साल 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे थे।

दूसरी ओर चांदी के वायदा भाव की शुरूआत कमजोर रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 842 रुपये की गिरावट के साथ 2,30,015 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 2,30,857 रुपये था। चांदी का वायदा भाव इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव में गिरावट रही है। कॉमेक्स पर सोना 4,106.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला।

सीमित बजट के लिए है ये पांच सस्ते और दमदार हैचबैक मॉडल्स

नई दिल्ली। यदि आप पहली बार कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट सीमित है, तो यहाँ ऑटो एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए पाँच सस्ते और दमदार हैचबैक मॉडल्स दिए गए हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो के10, जिसकी शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये है, में के10सी 3-सिलेंडर इंजन मिलता है जो 65.71बीएचपी की पावर और 89एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (एजीएस) दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है। रेनॉल्ट क्विड, 4.53 लाख रुपये की शुरूआती कीमत पर आती है, जिसमें 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (68.06बीएचपी/92.5एनएम) मैनुअल और एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है। हुंडई ग्रैंड 10 नियोस, 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है, कम बजट में प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए बेहतरीन है। इसमें 1.2-लीटर का चार-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन (81बीएचपी/113.8एनएम) मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी के साथ आता है। टाटा टियागो, जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, 4.69 लाख रुपये की शुरूआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (86बीएचपी/113एनएम) मैनुअल और पैडल शिफ्टर्स के साथ एएमटी गियरबॉक्स के विकल्पों के साथ आता है। अंत में, सिट्रोएन सी3एक्स, एंट्री-लेवल सेगमेंट में 4.99 लाख रुपये की शुरूआती कीमत के साथ एक दमदार लेकिन अंडररेटेड कार है।

यह दो इंजन विकल्पों के साथ आती है: एक 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (80.46बीएचपी) और दूसरा 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन (108.5बीएचपी) जो मजबूत परफॉर्मेंस देता है। बता दें कि शहर के भारी ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पेस में छोटी हैचबैक कारें आज भी सबसे व्यावहारिक विकल्प मानी जाती हैं।

ई-20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित : पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली। ई20 पेट्रोल को लेकर भ्रामक सूचनाओं के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इस पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं, जिसका विदेशों में भी वर्षों से सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार ने ई20 पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार ने उन दावों को महज अफवाह बताया, जिनमें पानी की बबार्दी, इंजन खराब होने या बीमा समाप्त होने की बात कही जा रही थी। इथेनॉल उत्पादन में पानी की बबार्दी के दावे को गलत बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि एक लीटर इथेनॉल बनाने में केवल 3 से 5 लीटर पानी लगता है, और नई फैक्ट्रियां इसे रीसायकल भी करती

हैं। इथेनॉल मुख्य रूप से देश की जरूरत से बचे अतिरिक्त चावल और अब 40 प्रतिशत से अधिक मक्के से बनता है, जिसकी खेती में कम पानी लगता है। इंजन खराब होने के डर पर, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टेस्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कारों को 40,000 किलोमीटर और बाइकों को 20,000 किलोमीटर चलाकर देखा गया। परीक्षणों में पाया गया कि गाड़ी के चलने या माइलेज पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इथेनॉल की बेहतर गुणवत्ता के कारण इंजन बेहतर काम करता है।

सरकार ने इस कार्यक्रम के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है, जिससे देश के 1.9 लाख करोड़ रुपये बचे हैं, किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिला है और लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि, बहुत पुरानी गाड़ियों में कुछ रबर के पुर्जे समय से पहले बदलने पड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे चीनी या कीड़े से संबंधित दावों को भी सरकार ने निराधार बताया। इथेनॉल को रिफाइन करते समय उसमें से चीनी पूरी तरह से निकाल दी जाती है, और इसमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

दुर्लभ वन्यजीव सेंडबोआ तस्करी मामले में आरोपियों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

- भोपाल। भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुर्लभ वन्यजीव सेंडबोआ की तस्करी से जुड़े लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में 2 आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपराध क्रमांक 59/2016 (दिनांक 22 अगस्त 2016) में 29 जून 2026 को सुनाया गया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश तथा क्राइम ब्रांच भोपाल को प्राप्त सूचना के आधार पर 22 अगस्त 2016 को राहुल नगर झुग्गी बस्ती स्थित मंदिर के पास मुख्य मार्ग से 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पूछताछ में उनकी पहचान भोपाल निवासी अमन वामने और वरुण विश्वकर्मा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद कपड़े के थैले से एक जीवित दुर्लभ वन्यजीव सेंडबोआ बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच ने वन्यजीव को विधिवत जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में

नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में बीच नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हो गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में केन्द्र एवं चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान का विवाद चल रहा था, जिसका आज सौहार्दपूर्ण समाधान निकल गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में डबल इंजन सरकार बनने का लाभ यह हुआ है कि हम में एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ी है, राजनीतिक मुद्दे कम हुए हैं और देश के अनेक विवाद अब तेजी से सुलझाए जा रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय परियोजना पर आम सहमति बनाने में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग की सराहना की। श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना से विशेषकर मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। बांध पूरा होने से इन राज्यों में हर जगह पानी और बिजली पहुंची। उन्होंने कहा कि राजस्थान को हुआ लाभ दिखने में छोटा लग सकता है, पर जिस भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचा है, वहां भूमि का मूल्य और किसान की किस्मत दोनों बदल गई है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जी के नेतृत्व में देश में चल रहे जल विवाद या जल वितरण से जुड़े विवाद एक-एक कर सुलझाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान के बीच का जल विवाद सुलझाया गया। श्री शाह ने कहा कि चाहे किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो या राजस्थान, हरियाणा के बीच जल विवाद हो या आज का यह समझौता, ये सभी सहकारी संघवाद के स्वर्णिम उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र, पानी देश के लोगों, खासकर किसानों के ही काम आता है। श्री शाह ने कहा कि पानी का उपयोग चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो उससे लाभान्वित होने वाला एक भारतीय ही होगा केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी विवाद से होने वाले राष्ट्रीय नुकसान को ध्यान में रख कर उसे सुलझाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी राज्य समृद्ध होता है, तो उसका लाभ अपने राज्य को भी मिलता है।

डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव

भोपाल। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के शक्ति भवन मुख्यालय में "साइबर सिक्योर 2026" अभियान के अंतर्गत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के विशेषज्ञों ने पावर सेक्टर में बढ़ते साइबर खतरों, साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उप पुलिस अधीक्षक राज्य साइबर पुलिस श्रीमती उमाकांती आर्मो के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने एम पी ट्रांसको के कार्मिकों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, मोबाइल एप्स के सुरक्षित उपयोग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड तथा साइबर ठगी के नए तरीकों से बचाव के बारे में प्रशिक्षित किया। साथ ही संदिग्ध कॉल, फर्जी लिंक, ई-मेल और डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला गया। साइबर विशेषज्ञ श्री मोहित पांडे ने पावर सेक्टर पर बढ़ते साइबर खतरों की चर्चा करते हुए साइबर सुरक्षा को ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साइबर फ्रॉड की स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। वहीं साइबर विशेषज्ञ श्री राज शर्मा ने एआई युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों, फर्जी ई-मेल से बचाव, प्रमाणित वेबसाइटों के उपयोग और संचार साथी ऐप की उपयोगिता पर जानकारी साझा की।

जवाहर बाल भवन के स्थापना दिवस समारोह का हुआ गरिमामय समापन

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री सुश्री भूरिया

भोपाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें एक सुरक्षित, सकारात्मक एवं प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के भीतर छिपी रचनात्मक प्रतिभा को सही मंच देना समाज और सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी है।

मंत्री सुश्री भूरिया मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित 'जवाहर बाल भवन, भोपाल' के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक प्रतियोगिताओं के गरिमामय समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने विभिन्न रचनात्मक विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया।

दशकों से प्रतिभाओं को निखार रहा है जवाहर बाल भवन

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुश्री भूरिया ने बच्चों की अद्भुत और बहुमुखी प्रतिभा की जमकर सराहना की। जवाहर बाल भवन वर्ष 1987 (स्थापना 3 जुलाई 1987) से ही लगातार 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की रचनात्मकता और उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने का एक सशक्त और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। इस वर्ष आयोजित 'समर कैम्प 2026' के अंतर्गत बच्चों के कौशल विकास के लिए विशेष और अत्याधुनिक कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जिससे बच्चों को अपनी कला को नया आयाम देने का मौका मिला। स्थापना दिवस के उपलक्ष में 3 जुलाई से लगातार संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाटक, गृह-विज्ञान, मूर्तिकला, हस्तकला, कम्प्यूटर, खेलकूद और आधुनिक अभिनय कला जैसी 10 से अधिक विभिन्न विधाओं के अंतर्गत साप्ताहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा था। इन प्रतियोगिताओं में शहर के सैकड़ों बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। समारोह में प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभावान बच्चों को मंच पर सम्मानित किया गया।

विकसित भारत के संकल्प से 2047 तक विश्वगुरु बनेगा भारत : उच्च शिक्षा मंत्री

इंदौर। भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदरसिंह परमार ने मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कही।

मंत्री परमार खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जनजातीय अध्ययनशाला की प्रथम बैच के पाठ्यक्रम पूर्णता समारोह और नवनिर्मित सभागृह के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें आध्यात्म और विज्ञान का बेहतर समन्वय किया गया है, जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. राकेश सिंघई और कुलसचिव प्रज्जवल खरे सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में स्थान देने पर जोर

मंत्री परमार ने कहा कि भारत की संस्कृति में प्रकृति संरक्षण की भावना सदियों से रही है। सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, वृक्ष और वनस्पतियों के प्रति सम्मान हमारी परंपरा का हिस्सा है, जिसका वैज्ञानिक आधार भी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज आज भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की सीख देता है। उन्होंने कहा कि भारत में चाणक्य, बोधायन और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान हुए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है और आने वाले समय में भारत ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के सामने रील बनाने और इतिहास बनाने, दोनों के विकल्प हैं।

खजराना सिविल अस्पताल के नाम पर कोई व्यय अथवा खरीदी नहीं

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सिविल अस्पताल खजराना के नाम पर अब तक किसी प्रकार की औषधि, चिकित्सा उपकरण अथवा अन्य सामग्री की खरीदी नहीं की गई है। अस्पताल के लिए किसी प्रकार का वित्तीय आवंटन भी नहीं किया गया है। अस्पताल भवन नहीं होने के कारण संस्था क्रियाशील नहीं हो सकी है। कोविड-19 के बाद बढ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए इन कर्मचारियों से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवाएं ली जा रही हैं। कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कार्य आवंटित किया गया है तथा नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2021 में खजराना सिविल अस्पताल के लिए कुल 87 पद स्वीकृत किए गए थे।

मध्यप्रदेश पुलिस की मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जनजागरूकता अभियान

भोपाल। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के निर्देशन में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही हैं। इसी क्रम में रीवा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की 3.087 किलोग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रदेश में नशे के अवैध नेटवर्क के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता है।

पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन श्री गौरव राजपूत एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा रेंज श्री हेमन्त सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त हुई है। जिले में संचालित ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत थाना गढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सोनवर्षा निवासी दो व्यक्ति भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स लेकर बिक्री के उद्देश्य से जाने वाले हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3.087 किलोग्राम अवैध एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है, जब्त की गई। इसके अतिरिक्त दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना गढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

मध्यप्रदेश पुलिस एक ओर जहां अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस आगामी 15 जुलाई से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान भी प्रारंभ करने जा रही है। इस अभियान के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्रामों, नगरीय क्षेत्रों, सामाजिक संस्थाओं तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए युवाओं को नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पुलिस ने 2,095 गुम एवं चोरी हुए मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाए

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। 24 जून 2026 से प्रारंभ इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलों, महाविद्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, शासकीय एवं निजी संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आमजन को संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, डिजिटल भुगतान के दौरान सतर्कता बरतने, ओटीपी एवं बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने तथा साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

साइबर अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ मध्यप्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग के माध्यम से गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाने का कार्य भी निरंतर कर रही है। उएक्क पोर्टल,

तकनीकी विश्लेषण तथा विभिन्न जिलों की साइबर टीमों के समन्वित प्रयासों से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए जा रहे हैं, जिससे आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।13 जूनसे अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं जीआरपी इकाइयों द्वारा कुल 2,094 गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोनबरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाए हैं। इनमें "सेफ क्लिक 2.0" अभियान प्रारंभ होने के बाद अब तक प्रदेश के 12 जिलों एवं 02 जीआरपी में कुल 1461 गुम मोबाइल फोनउनके वास्तविक स्वामियों को लौटाए गए हैं। इनमें भिंड ने 325, देवास ने 210,शाजापुर ने 179, नरसिंहपुर ने 175, छतरपुर ने 149,रायसेन ने 149,बड़वानी ने 129, भोपाल जीआरपी ने 124, खंडवा ने 123, खरगोन ने 100, बुरहानपुर ने 100,झाबुआ ने 80,सिंगरौली ने 70, गुना ने 65,भोपाल ग्रामीण ने 53, उज्जैन ने 40,कटनी ने 10,जबलपुर जीआरपी ने 7, इंदौर जीआरपी ने 5, सिवनी ने 1 तथा छतरपुर ने 1 मोबाइलशामिल है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून 2026 से संचालित "सेफ क्लिक 2.0" अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की बैठक में मंत्री परमार के निर्देश, ड्रग टेस्टिंग लैब और शोध पर भी जोर

इंदौर में बनेगा 50 बिस्तरीय आयुर्वेद सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

इंदौर। आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए इंदौर में 50 बिस्तरीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदरसिंह परमार ने मंगलवार को शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, लोकमान्य नगर में आयोजित साधारण सभा की बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री परमार ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, चिकित्सा सेवाओं और आगामी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परिसर का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवा को समर्पण भाव से अपनाने और मरीजों की बेहतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, विधायक महेंद्र हार्डिया, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजीतपाल सिंह चौहान सहित संस्था के सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

आयुर्वेद शोध और सुविधाओं के विस्तार पर जोर

मंत्री परमार ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए परिणाम आधारित कार्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों पर शोध को बढ़ावा दिया जाए, ताकि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा सके।

उन्होंने इंदौर में निजी औषधि निमार्ता कंपनियों की दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए महाविद्यालय में ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

100 पीजी सीटों के अनुसार बढ़ेगी फैकल्टी

मंत्री ने महाविद्यालय में शुरू की गई 100 स्नातकोत्तर सीटों के अनुपात में शिक्षण फैकल्टी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष अधिकारी गांवों में जाकर लोगों का प्रकृति परीक्षण करें और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के साथ रसोई में उपलब्ध मसालों के औषधीय उपयोग की जानकारी दें।

20 एकड़ भूमि पर विकसित होंगी नई सुविधाएं

बैठक में महाविद्यालय और चिकित्सालय के विस्तार के लिए करीब 20 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित भूमि पर अत्याधुनिक स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्र, ड्रग टेस्टिंग लैब, एनिमल हाउस, स्टाफ क्वार्टर, फामेर्सी, नक्षत्र गार्डन और वनौषधि उद्यान विकसित करने की योजना है। मंत्री परमार ने प्रस्तावित भूमि पर आवश्यक सुविधाओं के साथ निर्माण कार्य के लिए सहमति दी।

40 मरीजों की एक साथ जांच होगी

बैठक के दौरान अस्पताल में 6.50 लाख रुपये की लागत से स्थापित ऑटो एनालाइजर मशीन का शुभारंभ किया गया। इस मशीन से एक साथ 40 मरीजों के रक्त परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।